बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 167

भविष्य की चुनौतियां

आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानों ने अर्थव्यवस्था के जानकारों और पूर्वानुमान लगाने वालों को चौंकाया है। गत सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी जो पांच तिमाहियों में उच्चतम है। सकल मूल्य वर्धन को अर्थव्यवस्था का बेहतर संकेतक माना जाता है और उसमें 7.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तिमाही के लिए 6.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया था। बहरहाल, इस स्तर की वृद्धि को बरकरार रखना या रिजर्व बैंक के पूरे वर्ष के 6.5 फीसदी के लक्ष्य को हासिल करना विपरीत कारोबारी माहौल में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी हिस्सों ने वृद्धि को बल दिया। कृषि क्षेत्र पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.5 फीसदी की तुलना में 3.7 फीसदी की दर से बढ़ा। विनिर्माण क्षेत्र ने 7.7 फीसदी की दर से वृद्धि दर्ज की जबकि गत वर्ष की समान अवधि में यह 7.6 फीसदी की दर से बढ़ा था। सेवा क्षेत्र भी पिछले साल की तुलना में तेज गति से बढ़ा जबकि खनन और उत्खनन में कमी आई। निर्माण क्षेत्र में मंदी आई। उच्च वृद्धि को एक हद तक सरकारी व्यय से मदद मिली जो इस तिमाही में 7.4 फीसदी बढ़ा। गत वर्ष की पहली तिमाही में आम चुनाव के कारण सरकारी व्यय सीमित था। यह सरकारी खातों में भी नजर आया। केंद्र सरकार ने पहली तिमाही में वार्षिक पूंजीगत व्यय बजट का लगभग एक-चौथाई हिस्सा खर्च किया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह केवल लगभग 16 फीसदी था।

पहली तिमाही के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं जबकि यहां से हालात कठिन हो सकते हैं। वृद्धि के समक्ष सबसे बड़ा जोखिम अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों का है। अनुमान बताते हैं कि करीब 66 फीसदी भारतीय निर्यात को 50 फीसदी या उससे अधिक शुल्क का सामना करना होगा। वृद्धि पर इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह शुल्क कितने लंबे समय तक लागू रहता है। अगर इस स्तर का शुल्क कुछ तिमाहियों तक भी लागू रहा तो यह रोजगार और घरेलू मांग को प्रभावित करना शुरू कर देगा। सरकार जहां इसके असर को कम करने को लेकर काम कर रही है, वहीं मांग को पहुंचे संभावित नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी। ऐसे में आने वाली तिमाहियों में वृद्धि मोटे तौर पर भारत-अमेरिका रिश्तों में सुधार पर निर्भर होगी। इसके अलावा, वर्तमान तिमाही की वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि कई परिवार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संभावित कटौती की उम्मीद के चलते अपने खरीदारी के फैसले टाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कारों सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की संभावना है। हालांकि, इसका असर केवल एक तिमाही तक सीमित रह सकता है, क्योंकि जैसे ही जीएसटी दरें समायोजित होंगी, मांग फिर से बढ़ जाएगी।

मांग से जुड़ी चिंताओं के अलावा एक और बड़ी समस्या है नॉमिनल वृद्धि की कमी। वर्तमान कीमतों पर, पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि केवल 8.8 फीसदी रही। चूंकि आने वाली तिमाहियों में महंगाई दर कम रहने की संभावना है, ऐसे में नॉमिनल वृद्धि इसी स्तर पर या इससे भी कम रह सकती है। ऐसे में राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करना कठिन हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, आगामी जीएसटी समीक्षा से राजस्व पर भी असर पड़ सकता है, कम से कम अल्पकालिक रूप में। ऐसे में सरकार को कई उभरती चुनौतियों का समाधान करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष साबित हो सकता है, जिसमें सरकार को बेहद सतर्कता से कदम उठाने होंगे।

एफपीआई क्यों कर रहे हैं बिकवाली?

मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल मंदी की भावना को मजबूत करता है लेकिन शेयर बाजार में विशुद्ध प्रवाह के शून्य होने की प्राथमिक वजह यह नहीं है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश

विगत पांच वर्षों से भारत में सार्वजनिक इक्विटी यानी शेयर बाजारों में शुद्ध विदेशी निवेश शून्य रहा है। यह अवधि असाधारण रूप से लंबी है। इस वर्ष भी निवेश प्रवाह में 13 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयरों में विदेशी स्वामित्व पिछले 15 साल में सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। भारत अब एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां सभी क्षेत्रीय, वैश्विक और उभरते बाजारों वाले फंड्स ने अपने निवेश को कम कर दिया है। दूसरी तरफ, पांच वर्ष की इस अवधि में घरेलू निवेश प्रवाह 185 अरब डॉलर से अधिक रहा है। जिस समय विदेशी निवेशकों की रुचि कम हो गई, उसी समय घरेलू निवेशक पहले से कहीं अधिक आशावादी और सक्रिय हो गए हैं।

विदेशी पूंजी की निवेश में रुचि घटने की क्या वजह हो सकती है? इसकी एक आंशिक वजह उभरते बाजारों की परिसंपत्तियों के प्रति घटती रुचि है। उभरते बाजारों की इक्विटी में निवेश करना पिछले कुछ वर्षों में बेहद निराशाजनक रहा है। इसने अमेरिका और वैश्विक इक्विटी की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन किया है। यदि किसी ने 15 वर्ष पहले उभरते बाजारों की इक्विटी में 100 डॉलर का निवेश किया होता, तो आज उसकी कीमत लगभग 180 डॉलर होती, जबकि वही राशि यदि वैश्विक सूचकांकों में निवेश की जाती, तो आज लगभग 500 डॉलर होती। हालांकि, इस नजरिये से देखें तो भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले पांच वर्षों में एमएससीआई इंडिया ने डॉलर में लगभग 15 फीसदी का वार्षिक रिटर्न दिया है, जबकि व्यापक ईएम सूचकांक ने मात्र 5 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कई निवेशकों ने उभरते बाजारों की परिसंपत्ति में भरोसा गंवा दिया है और अपना निवेश कम किया है जबकि अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत फंडिंग का जरिया बना रहा। भारत की तेजी में अमेरिकी एंडोमेंट और फाउंडेशनों की अहम भूमिका रही लेकिन इस समय वे नकदी संकट से जूझ रहे हैं। निजी परिसंपत्तियों में अत्यधिक निवेश के कारण उनकी परिसंपत्ति और देनदारी में विसंगति उत्पन्न हुई और उन्हें सार्वजनिक इक्विटी बेचकर पूंजी जुटाने पर विवश होना पड़ा। भारत फंडिंग का स्वाभाविक स्रोत बना रहा क्योंकि उसका प्रदर्शन और मूल्यांकन लगातार ऊंचा रहा।

गत 12 से 18 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमापन आया है। वृद्धि स्पष्ट रूप से एक चुनौती है। अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है। हम 6 फीसदी की वृद्धि हासिल करने में भी जूझते नजर आ रहे हैं। इससे यह साफ है कि कारोबारी आय प्रभावित हुई है। प्रति शेयर कमाई में वृद्धि इस वर्ष करीब 10 फीसदी के आसपास रहेगी। 20 गुना अग्रिम आय पर कारोबार कर रहे बाजार के लिए आय संबंधी निराशा झेलना आसान नहीं। हम केवल 10 फीसदी की प्रति शेयर कमाई वृद्धि के साथ दुनिया का दूसरा सबसे महंगा बाजार नहीं रह सकते।

कई निवेशकों का मानना है कि हाल तक, आत्मसंतुष्टि की भावना थी, तथा वृद्धि को गति देने की कोई ठोस योजना नहीं थी। आर्थिक सुधारों के मामले में सरकार का तीसरा कार्यकाल पूरी तरह धीमी गति से शुरु हुआ। वृद्धि के टिकाऊपन को लेकर निश्चिंत न होने के कारण कई निवेशकों ने मुनाफा कमाया और भारत में अपने निवेश को कम किया। भारत के मूल्यांकन प्रीमियम को तब तक उचित नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि हमें पूरी तरह यह यकीन न हो कि यह आर्थिक वृद्धि और आय दोनों मामलों में आगे रहेगा। गत दो वर्षों में देश के दीर्घकालिक आर्थिक प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं क्योंकि सुधार नजर नहीं आ रहे हैं।

भारत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। चैटजीपीटी के आगमन के बाद से ही एआई कंपनियों के शेयर एसऐंडपी 500 के रिटर्न में 50 फीसदी से अधिक के हिस्सेदार रहे। आज आठ शेयर जिनमें सभी एआई कंपनियों के है, अमेरिकी बाजार पूंजीकरण में 35 फीसदी से अधिक के हिस्सेदार हैं। अकेली कंपनियां शोध एवं बाजार पूंजीकरण पर 75 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर रही हैं। अमेरिका और चीन को छोड़कर कोई देश एआई के मामले में मुकाबले में नहीं है।

भारत के समक्ष एक प्रश्न आईटी सेवा उद्योग के भविष्य का भी है। देश के आईटी क्षेत्र में 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह क्षेत्र रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा कारक रहा है। कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र में सालाना 2-2.50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा रहा था। अब यह घटकर 50 हजार रह गया है। कुछ लोगों को डर है कि आने वाले पांच साल में इस उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में और कमी आएगी। टीसीएस द्वारा की गई हालिया छंटनी की घोषणा एक बानगी है। जैसे-जैसे औद्योगिक वृद्धि में धीमापन आएगा और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में उच्च वेतन वाले मझोले प्रबंधकीय रोजगार भी छिनेंगे। सालाना 200 अरब डॉलर का निर्यात करने वाले इस क्षेत्र में वृद्धि दर के पांच फीसदी से कम होने का क्या असर होगा? भारत में कम लागत में काम करने वाले कुशल कर्मचारी बहुत हैं जो उसे प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाते हैं। बहरहाल, एआई कुशल कर्मचारियों की जरूरत को कम करता है। क्या यह देश की दीर्घकालिक वृद्धि पर असर डालेगा?

यह याद रखना उचित होगा कि हमें गत पांच साल में शुद्ध रूप से कोई एफपीआई नहीं मिला है। मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव इसकी वजह है लेकिन यह इकलौती वजह नहीं है। घरेलू इक्विटी की आवक की प्रकृति अधिक ढांचागत है। आज भी यानी शून्य रिटर्न के एक साल बाद भी इसमें इजाफा हो रहा है। जब विदेशी खरीदार लौटते हैं तो इसका कीमतों पर विसंगतिपूर्ण असर हो सकता है। हम भूल गए हैं कि जब विदेशी और स्थानीय निवेशक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में खरीद करते हैं तो बाजार कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा पांच साल से नहीं हुआ है।

डॉलर इस साल 10 फीसदी तक गिर चुका है। गैर अमेरिकी इक्विटी में निवेश संभावना सुधर रही है। ऐसे में आने वाले समय में उभरते बाजारों की इक्विटी में निवेश बढ़ेगा। हालांकि, यदि भारत को अपने हिस्से से अधिक निवेश आकर्षित करना है, तो वैश्विक निवेशकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम 7-8 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर लंबे समय तक टिकाऊ रूप से हासिल कर सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ कंपनियों की प्रति शेयर आय में भी वृद्धि होगी।

चूंकि घरेलू निवेश प्रवाह मजबूत है, इसलिए यह संभावना कम है कि बाजारों में मूल्य के स्तर पर कोई बड़ी गिरावट आएगी। वे पहले ही कई नकारात्मक खबरों को झेल चुके हैं। इसलिए, भारतीय इक्विटी में निवेशकों की वापसी तभी संभव होगी जब वे उच्च मूल्यांकन प्रीमियम को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह भुगतान करने की इच्छा तब आएगी जब निवेशकों को यह विश्वास हो कि भारत अगले 20 वर्षों तक 7 फीसदी की आर्थिक वृद्धि बनाए रख सकता है।

ऐसे हालात में मौजूदा भू-राजनीतिक कठिनाइयों को एक चेतावनी और अवसर दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। जरूरी सुधारों के बारे में हम सभी जानते हैं। अब वक्त है पहल करने का। हमें इसे आर्थिक संकट मानते हुए दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी सुधारने के लिए काम करना चाहिए। बीते कुछ सप्ताहों ने यह भी दिखाया है कि केवल आर्थिक सहूलियत ही मायने रखती हैं। हमारे पास यह बहुत कम है। यह मायने नहीं रखता कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। सवाल यह है कि हमारा प्रभाव क्या है? हमें कुछ विशेष उद्योगों में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो हमारे पास कभी भी पर्याप्त प्रभाव नहीं होगा।

चीन का प्रभाव केवल दुर्लभ खनिज तत्वों तक सीमित नहीं है। उसका प्रभाव इस तथ्य में भी है कि वह वैश्विक विनिर्माण मूल्यवर्धन में 35 फीसदी हिस्सा रखता है। यह उसके बाद के 10 देशों के संयुक्त योगदान के बराबर है। हम उस स्तर की विशालता की आकांक्षा नहीं कर सकते, लेकिन यदि सोच-समझकर प्रयास किया जाए, तो वैश्विक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें हमें प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिल सकता है।

(लेखक अमांसा कैपिटल से जुड़े हैं)

भारत के लिए चेतावनी है शुल्क का झटका

भारतीय निर्यात पर अब अमेरिका में 50 फीसदी का आयात शुल्क (टैरिफ) लग रहा है। यह दुनिया के लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में एक बड़ी बाधा है। नतीजतन, सरकार को यह विचार करना होगा कि इससे कैसे निपटा जाए। हालांकि सरकार को राजनीतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह लक्ष्य स्पष्ट है कि नुकसान कम करना है ताकि भारत तेजी से विकास के रास्ते पर लौट सके। हालांकि यह काम जटिल है क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था में चुनौती के साथ विदेशी बाजारों में भी संभावनाएं कम हो गई हैं।

आखिर टैरिफ का झटका वास्तव में कितना गंभीर है? कई विश्लेषकों का तर्क है कि इसका असर सीमित होगा। वे बताते हैं कि अमेरिका को होने वाला वस्तुओं का निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सिर्फ 2 फीसदी है और इसमें से भी केवल दो-तिहाई ही प्रभावित होगा, क्योंकि दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों को छूट दी गई है।

हालांकि, यह तर्क बड़ी तस्वीर को अनदेखा करता है। अमेरिका सिर्फ भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार नहीं है बल्कि यह एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार भी है। नतीजतन, टैरिफ का झटका सिर्फ व्यापार को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह निवेशकों के भरोसे को हिला देगा और इससे आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित होगी और भारत की दीर्घकालिक निर्यात प्रतिस्पर्धा भी कमजोर होगी। असली जोखिम इन दूरगामी प्रभावों में निहित है, जो तात्कालिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, तीन तरह की कंपनियों की स्थिति पर विचार करते हैं।

इस कड़ी में सबसे पहले और स्पष्ट तौर पर प्रभावित होने वालों में वैश्विक निर्माता कंपनियां शामिल हैं। भारत खुद को अगले वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश कर रहा था, खासतौर पर उन कंपनियों के लिए जो अमेरिका को निर्यात करती हैं या चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयां हटाना चाहती हैं। इसे भारत की वृद्धि के लिए संभावित तौर पर खेल में बदलाव लाने वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था। एक युवा और तेजी से कुशल हो रहे कार्यबल तथा लोकतांत्रिक स्थिरता के साथ, यह लाभ स्पष्ट रूप से दिख रहा था। हालांकि, 50 फीसदी के अमेरिकी शुल्क ने अब इस फायदे को खत्म कर दिया है।

अमेरिका ने 7 अगस्त को जो जवाबी 25 फीसदी का टैरिफ लगाया था अगर उतना ही रहे तो भी भारत अपने एशियाई प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी रहेगा क्योंकि उनके अमेरिकी निर्यात पर केवल 19-20 फीसदी टैरिफ लगता है। यदि यह अंतर बना रहता है, तब भारत के लिए दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने का एक दुर्लभ मौका खोने का जोखिम बना हुआ है।

सिर्फ माल निर्यातकों को ही नुकसान नहीं होगा। इसका असर सेवा निर्यातकों पर भी दिख सकता है। भारत के 1,700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में से लगभग 60 फीसदी का मुख्यालय अमेरिका में है। हालांकि टैरिफ सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित नहीं करते, लेकिन अमेरिका-भारत संबंधों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ये मूल कंपनियां यहां अपना कारोबार बढ़ाने में सतर्कता बरत सकती हैं। यह वास्तव में एक गंभीर झटका होगा क्योंकि कोविड के बाद भारत के विकास में सेवा निर्यात एक प्रमुख आधार रहा है।

आखिर में घरेलू विनिर्माताओं पर विचार करते हैं। वे भले ही ज्यादा निर्यात न करते हों, लेकिन इनमें से कई विदेशी कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अगर भारत अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने के बारे में सोचता है तब इससे उनके निवेश की योजनाएं और भी रुक सकती हैं।

राजेश्वरी सेनगुप्ता

ऐसे में, टैरिफ का यह झटका पूरी अर्थव्यवस्था में फैलने का जोखिम रखता है। इसके अलावा, तेजी से सामने आने वाले आंकड़े भी पहले से ही आर्थिक सुस्ती की ओर इशारा कर रहे हैं। गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि एक साल पहले के 14 फीसदी से घटकर 10 फीसदी पर आ गई है। अप्रैल-जून में वस्तुओं का निर्यात केवल 2 फीसदी बढ़ा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में बढ़त 11 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गया है। यात्री वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट आई है, जो शहरी मांग में सुस्ती को दर्शाती है। पिछले कुछ सालों की रियल एस्टेट में आई तेजी थम सी गई है जिससे प्रमुख शहरों में वैसे घरों की तादाद बढ़ रही है जो बिके नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, अमेरिका का यह टैरिफ झटका ऐसे समय में आया है, जब स्थिति पहले से ही बहुत खराब है।

भारत को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत को आत्मनिर्भर होने की आत्ममुग्धता में नहीं पड़ना चाहिए। संरक्षणवाद से कभी भी तेज विकास नहीं हुआ है और 1991 से पहले के भारत का अपना रिकॉर्ड इसका प्रमाण है और किसी भी अन्य देश को उस तरह से सफलता नहीं मिली है। भले ही अमेरिका का झुकाव अब संरक्षणवाद की ओर हो रहा हो, लेकिन भारत इस गलती को दोहरा नहीं सकता।

आत्मनिर्भर होने के बजाय, भारत को कई अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को गहरा करके अपने निर्यातकों की मदद करनी चाहिए। ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता एक स्वागत योग्य कदम है जबकि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ बातचीत बेहद महत्त्वपूर्ण है और इसे तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। भारत को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ भी समझौते करने चाहिए ताकि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूती से जुड़ सके। इसका मतलब होगा कि भारत को अपनी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम करनी होंगी जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आत्मनिर्भरता की रणनीति खुद को हराने वाली साबित होगी।

इसी के साथ, भारतीय नीति-निर्माताओं को सिर्फ समस्याओं से निपटने के बजाय ऐसे सुधारों को लागू करना चाहिए जो भारत की विकास क्षमता को उजागर करें। इसके साथ ही निजी निवेश को फिर से बढ़ाने, विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके तैयार करने के लिए सरकारी लालफीताशाही को कम करना, नियमों को सरल बनाना, व्यापार सुगमता की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचे में ही नहीं, बल्कि कौशल विकास में भी निवेश करना जरूरी होगा। हाल की घोषणाएं जैसे कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाना और एक सुधार समिति का गठन करना बेहद उत्साहजनक हैं, लेकिन असली परीक्षा इन सुधारों के ब्योरे और सबसे बढ़कर इनके क्रियान्वयन में होगी।

अंत में, इस झटके के कारण भारत को अमेरिका-विरोधी रुख अपनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ऐसे संबंधों में टकराव होना तय है लेकिन अमेरिका एक आर्थिक भागीदार के रूप में इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। भारत का दीर्घकालिक उद्देश्य, बेहतर और व्यापक व्यापार समझौतों पर बातचीत करके अमेरिका के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना होना चाहिए, न कि उसे कमजोर करने पर होना चाहिए।

कई मायनों में, यह भारत के लिए यह दूसरा 1991 जैसा क्षण हो सकता है। इस बार संकट उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दांव उतने ही बड़े हैं। अर्थव्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है और अभी की गई कोई भी नीतिगत गलती भारत को दशकों तक निम्न-मध्यम-आय वाले देश के दर्जे में रहने के लिए मजबूर कर सकती है।

(लेखिका आईजीआईडीआर में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

आपका पक्ष

तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक विकास का प्रमुख साधन

अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं होने के कारण हमारे उद्योग अपने उत्पादों को विश्वस्तरीय बना पाने में नाकाम हो रहे हैं। सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उद्यमी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतः केंद्र द्वारा इन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी नीतिगत कदम उठाने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ये उद्यम न केवल शहर में बल्कि कस्बों और गांवों में भी सबसे बड़े रोजगार सृजक है। वर्तमान बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आसानी से ज्यादा कर्ज दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उनकी समस्या कर्ज नहीं, वह तकनीक है, जिसके अभाव में उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। जी-20 देशों के समूह की भारत की अध्यक्षता के बाद कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए गए थे जिसमें तकनीक में मानव केंद्रित रुख अपनाने और डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना, वित्तीय समावेशन तथा तकनीक सक्षम विकास वाले क्षेत्रों मसलन, कृषि से लेकर शिक्षा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ज्ञान की साझेदारी को बढ़ाना है। तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास का एकमात्र निर्धारक माना जा सकता है। अल्प विकसित देशों में वैज्ञानिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी की न केवल कमी है, बल्कि तकनीकी परिवर्तन लाने की पहल और उसके लिए उपयुक्त संस्थानिक ढांचे का अभाव भी होना है। विकसित देशों में वास्तविक आय में होने वाली तीव्र वृद्धि-दर अकेले पूंजी निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तो काफी हद तक उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम है जो स्वयं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अमेरिकन अर्थव्यवस्था है, जिसके विकास के लगभग दो-तिहाई भाग का श्रेय तकनीकी प्रगति को प्राप्त है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

वर्तमान बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आसानी से ज्यादा कर्ज दिए जाने का प्रावधान किया गया है

ट्रंप शुल्क की मार, भारत-चीन का साथ

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कुछ देशों में अधिक शुल्क लगाने के बाद भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध तेज होने लगे हैं। ट्रंप ने चीन पर भी अधिक टैरिफ लगाया है। विश्व की महाशक्ति देश से मुकाबला करने के लिए भारत और चीन अपनी आपसी दुश्मनी जैसे सीमा विवादों के सुलझाने के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच विवादों के समाधान के बढ़ते कदम के साथ ही आपसी रिश्तों में सुधार आना शुरू हो गया है। भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के लिए भी बात चल रही है। चीन भारत का पड़ोसी देश है और समय-समय पर भारत के भूभाग पर अपना दावा करता आया है। अब जब ट्रंप ने दोनों देशों पर उच्च टैरिफ लगा दिया है तो भारत-चीन मिलकर इसका सीधा मुकाबला कर सकते हैं। ट्रंप शुल्क से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत दूसरे देशों में नए अवसर तलाश सकता है। इसके साथ ही चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

उत्तरी गाजा क्षेत्र में रविवार को इजरायली हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। इजरायल के रक्षा मंत्री ई काट्ज ने रविवार को घोषणा की कि हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदा को इस सप्ताहांत गाजा में मार गिराया गया।

राष्ट्रीय सहारा

पटना • सोमवार • 1 सितम्बर • 2025

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

थोड़े दिन रहने वाली विपत्ति अच्छी है क्योंकि उसी से मित्र और शत्रु की पहचान होती है।

-रहीम

जापान के साथ अहम संधि

जापान ने भारत में एक दशक में 10 हजार अरब येन (करीब 60 हजार करोड़ रुपये) के निवेश का लक्ष्य रखा है, और दोनों देशों ने महत्त्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दस वर्षीय बड़ी रूपरेखा भी तैयार की है। दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों और दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जापान ने यह फैसला व्यापार और शुल्क पर अमेरिकी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के चलते वैश्विक पटल पर मची उथल-पुथल के बीच किया। भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के विस्तार की घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के बीच शिखर वार्ता के बाद की

गई। प्रधानमंत्री मोदी दो देशों-जापान और चीन-की अपनी यात्रा के पहले चरण में जापान पहुंचे थे जहां जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता हुई। शिखर वार्ता के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की 'निर्बाध और खुले हिन्द-प्रशांत' की अवधारणा और इस बाबत भारत की सोच में गहरा सामंजस्य है। 'विजन महासागर' और हिन्द-प्रशांत महासागरों की पहल से भारत की सोच मुखर होती है। दोनों देश शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत और व्यापक संबंध भी हैं। इसके चलते दोनों देशों को अपने साझा उद्देश्यों को अभिव्यक्ति देने के लिए हिन्द-प्रशांत देशों में से कुछ के साथ बहुपक्षीय प्रारूपों में संवाद करने में मदद मिलती है। बेशक, भारत और जापान ने अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में एक नये और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत-जापान की साझेदारी न केवल इन दोनों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बरक्स जापान और भारत का परस्पर सहयोग बढ़ना इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के बीच हुए समझौतों से इस तथ्य की तस्दीक होती है कि मजबूत लोकतंत्र बेहतर दुनिया को आकार देने में स्वाभाविक साझेदार होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इन दो प्रमुख एशियाई देशों की यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है। ऐसे में जापान-भारत के बीच साझेदारी का फैसला बेशक, आश्वस्त करने वाला है।

दीवारें लांघेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने को लेकर सरकार द्वारा अपनाई गई मानव संचालन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मांगी। केंद्र से पूछा क्या वह अवैध प्रवासियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर दीवार बनाना चाहता है। पीठ ने बंगाली व पंजाबीभाषी भारतीयों की पड़ोसी मुल्कों के साथ साझा सांस्कृतिक व भाषाई विरासत की भी चर्चा की। पीठ ने स्वीकारा कि पीड़ित संसाधनों की कमी के अभाव में शीर्ष अदालत पहुंचने में असमर्थ हैं। सरकार की तरफ से दी गई दलील में एजेंटों के अवैध प्रवेश

करवाने की बात की गई और कहा गया कि वे हमारे संसाधनों को नष्ट न करें। इस पर अदालत ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता व संसाधनों का सवाल है पर बंगाल व पंजाब की साझी विरासत पर केंद्र अपनी स्थिति स्पष्ट करे। बीते दिनों प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि केंद्र द्वारा बंगाली भाषाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। बहस के दरम्यान केंद्र की तरफ से रोहिंग्याओं का जिक्र भी हुआ जिनके साथ आतंकवादियों के घुसपैठ का भी संदेह जताया गया। अवैध प्रवासियों के चोरी-छिपे पड़ोसी मुल्कों में प्रवेश को लेकर दुनिया भर की सरकारें त्रस्त हैं। देश भर के सत्रह राज्यों में घुसपैठियों के रहने की बात सरकार द्वारा स्वीकारी जाती है। पंजाबी या बंगाली बोलने वालों को भारतीयों के साथ घुलने-मिलने में दिक्कत भी नहीं आती। जाहिर है, इनमें से कुछ रोजगार व सुरक्षा की तलाश में घुसते हैं। मगर अराजकता फैलाने व आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की मंशा से गलत तरीकों से सीमा पार करने वालों की भी कमी नहीं है। बार-बार दोहराया जाता है कि अकेले दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों के देश में रहने की चर्चा होती रहती है जिनमें से तकरीबन आधे पश्चिम बंगाल में ही लुक-छिप कर रह रहे हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। केंद्र द्वारा बनाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विरोध के साथ ही राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के हवाले से बयानबाजियां करते रहे हैं। बेशक, धरपकड़ अभियानों द्वारा मुट्ठी भर घुसपैठिये ही पकड़ में आते हैं। इन्हें रोकने के लिए न तो दीवारें उठाई जा सकती हैं, न ही अभी अवैध घुसपैठियों को एक ही लाठी से हांका जा सकता है, जो कंटीली बाड़ों और मुस्तैद सुरक्षा-व्यवस्था के बावजूद घुसपैठ करते हैं, वे दीवारें लांघने में क्यों घबराएंगे।

परिधि/राजीव मंडल

क्रोध का गला घोंटना होगा

कहा गया है कि 'क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है।' वाकई में क्रोध वह आंधी है, जिसके असर में विवेक खत्म हो जाता है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को घटित दो घटनाएं क्रोध के कारण सब कुछ बर्बाद करने का सर्वोत्तम उदाहरण है।

पहली घटना, कालकाजी मंदिर के प्रांगण में हुई। मंदिर जहां लोग परेशानियों और तनाव को भूलकर सिर्फ आराध्य की अराधना के लिए जाते हैं। मगर कालकाजी मंदिर में कुछ कूढ़मगज लोगों को इस फलसफे पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। यही वजहह है कि 'प्रसाद' और 'चुनरी' न मिलने से क्रोधित होकर उन्होंने सेवादार की लाठी-डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। क्या सभ्य समाज में ऐसी धृष्टता की कोई जगह है? क्या कोई गुस्से में आकर सिर्फ प्रसाद और माता की चुनरी के कारण किसी को मौत के घाट उतार सकता है। शायद नहीं! इसके पीछे एक वजह कानून का डर न होने की दलील दी जा सकती है, किंतु संस्कार और पारिवारिक-सामाजिक माहौल की अनदेखा नहीं की जा सकती है। बच्चों की परवरिश कैसे हुई है, उसकी पढ़ाई-लिखाई कहां से हुई आदि। सही कहा है किसी ने, 'क्रोध को थामे रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है; जलना आप ही को पड़ता है।' दूसरी वारदात, रोहिणी की है, जहां एक शख्स ने जन्मदिन की गिफ्ट को लेकर हुए मामूली से विवाद में अपनी पत्नी और सास की कैंची से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। अब इसे क्या कहा जाए? निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में धैर्य की घनघोर कमी है। इस तरह की घटना इक्का-दुक्का होती तो गनीमत रहती। बेहद साधारण सी बातों पर लोगों का खून खौलना और सामने वाले का खून बहा देने की प्रवृत्ति हाल के वर्षों में ज्यादा देखने को मिल रही है। जबकि जनता धर्म और आस्था के ज्यादा करीब हुई है। आमजन में भगवान की अराधना का भाव ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इसके बावजूद किसी की जान ले लेने के व्यवहार ने मानविकी के विशेषज्ञों को यह सोचने पर तो विवश कर ही दिया है कि आखिर गलती कहां हो रही है। बहरहाल, हमें इस मसले पर गहन मीमांसा करने की दरकार है कि लोग क्रोध में अपना, अपने परिवार का और अन्य किसी के साथ ऐसा कुछ न कर दें कि जीवनभर पछताने के सिवा और कुछ हासिल न हो। इस बारे में संजीदगी से विचारने की जरूरत है।

खास क्यों हैं उनका सामान

गुमनामी बाबा

विनीत नारायण

पिछले हफ्ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में इस कॉलम में जो मैंने लिखा था उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस विषय में यूट्यूब पर तमाम इंटरव्यू व रिपोर्ट्स हैं। वहां आप 'गुमनामी बाबा' या 'सुभाष चंद्र बोस' टाइप करके उन्हें देख सकते हैं। विशेषकर अनुज धर, चंद्रचूड़ घोष, शक्ति सिंह, डॉ दिनेश सिंह तोमर आदि के इंटरव्यू व जीटीवी पर एक 'गुमनामी बाबा का बॉक्स नंबर 26' जैसी रिपोर्ट्स देख, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पिछले लेख में मैंने उनके कमरे से मिली 2760 वस्तुओं में से कुछ का जिक्र किया था। यहां उन सामानों में से कुछ और का विस्तार से वर्णन कर रहा हूं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 'गुमनामी बाबा' नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो और कौन थे?

'गुमनामी बाबा' के कमरे में अंग्रेजी, बंगला व संस्कृत साहित्य की 304 पुस्तकें मिली हैं। 260 आध्यात्मिक पुस्तकें भी मिली हैं। मेडिकल साइंस पर 118, राजनीति व इतिहास पर 57, रहस्य और तंत्र शास्त्र पर 46, रामायण व महाभारत पर 36, सुभाष चंद्र बोस पर 34, यात्रा वृत्तांत ग्रन्थ 33 व ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान पर 12 पुस्तकें मिली हैं। अब जरा अंग्रेजी की पुस्तकों के लेखकों नाम और उनके लिखे ग्रंथों की संख्या देखिए, चार्ल्स डिकेंस (51), अलेक्सांद्र सोल्जेनित्सिन (11), विल ड्यूरांट (11), शेक्सपियर का लिखा संपूर्ण साहित्य व 9 नाटक, टी. लोबसांग रम्पा (10), वाल्टर स्कॉट (8), अलेक्जेंडर डुमास (8), एरिक वॉन डेनिकेन (4), पीजी वोडहाउस (3), कुलदीप नैयर (3) आदि पुस्तकें उनके बक्सों और अलमारी से निकली हैं। ऐसे उच्च कोटि के विश्वविख्यात साहित्य को पढ़ने वाला कोई भजनानंदी साधु नहीं हो सकता।

उपरोक्त साहित्य के अलावा, उनके कमरे से रीडर्स डाइजेस्ट, अमेरिकी पत्रिका टाइम, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ब्लिट्ज, ऑर्गेनाइजर, जुगवाणी, द पायनियर, आज, अमृत प्रभात, अमृत बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, दैनिक जागरण, द स्टेट्समैन, टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया व अमर उजाला जैसी तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाएं और अखबार भी मिले हैं। उनके बक्से में से उनके परिवार व निकट के लोगों के 110 चित्र मिले हैं जिनमें नेताजी के माता-पिता का फ्रेम करा हुआ चित्र, मखमली कपड़े में लिपटा उनके बक्से में रखा था। शक्ति सिंह के अयोध्या स्थित घर, 'राम भवन' के जिस कमरे में गुमनामी बाबा रहते थे, में दीवार पर मां काली का चित्र टंगा था जिनकी वे रोज धूप-बत्ती जला कर पूजा करते थे।

रोचक बात यह है कि 23 जनवरी को देश भर में जहां भी उनका जन्मदिन मनाया जाता था

उसकी खबरों में से सुभाष चंद्र बोस की फोटो निकाल कर संग्रह की गई हैं। इसी बक्से से नेताजी की बचपन से मित्र रहीं और क्रांतिकारी संगठन की नेत्री सुश्री लीला रॉय, पंडित नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद और महात्मा गांधी के चित्र भी मिले हैं। उनके संगीत संग्रह में महिषासुरमर्दनी स्रोत की रिकॉर्डिंग, रवींद्र संगीत, नजरुल इस्लाम, श्यामा संगीत, केएल सहगल, ज्योतिका रॉय, उस्ताद फैयाज खान, पं रविशंकर का सितार वादन, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, नेताजी के बचपन से मित्र और मशहूर गायक दिलीप कुमार रॉय के गाए गीत, हेमंत कुमार के गीत, पन्नालाल घोष, लालन फकीर आदि की गायकी के रिकॉर्ड भी मिले हैं। बॉलीवुड की फिल्म 'सुभाष चंद्र बोस' का पूरा साउंडट्रैक भी मिला है।

इंग्लैंड के टाइपराइटर और जर्मनी की बनी दूरबीन, जापानी क्रॉकरी, दो महंगी घड़ियां, जिनमें से एक थी सोने की बनी ओमेगा घड़ी जो बिल्कुल वैसी है जैसी नेताजी की मां ने उन्हें जन्मदिन पर भेंट की थी जिसे वो अक्सर पहना करते थे। दूसरी महंगी घड़ी रोलेक्स की है। गोल फ्रेम के 8 चश्में जिनमें से एक का फ्रेम शायद सफेद सोने का है। इन सब सामानों में सबसे भावुक वस्तु है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता श्री जानकी नाथ बोस की पुरानी छतरी जो, उनकी यादगार के प्रतीक रूप में गुमनामी बाबा ने सहेज कर रख रखी थी। इस छतरी को नेता जी के भतीजी ललिता बोस ने पहचाना।

उनके कागजों में अयोध्या व काशी के विस्तृत नक्शे, भारत के सड़क मार्गों व फौजी ठिकानों के नक्शे, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के नक्शे, जिन्हें हाथ से बनाया गया था, भी वहां बरामद हुए हैं। उनके सबसे प्रिय साथी पवित्र मोहन रॉय की संपत्तियों के नक्शे व एक अन्य साथी अतुल कृष्ण गुप्तो की ढाका में छूट गई संपत्ति के नक्शे आदि भी मिले हैं। उनके रहन-सहन का स्तर दर्शाते हुए उनके कमरे से नहाने के 75 साबुन मिले हैं, जो महंगे ब्रांड के हैं, जैसे यार्डले, क्यूटीक्यूरा, पियर्स, पोंड्स, लेवेंडर व इयु आदि। सबको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस 'चेन स्मोकर' थे। लगातार सिगरेट पीते थे। उनके सामानों में 'गोल्ड फ्लैक' व 'इंडिया किंग्स', सिगरेट के कई पैकेट, रोल बनाकर सिगरेट बनाने वाले कागज के 15 पैकेट व इन कागजों में भरने वाले तंबाकू के पैकेट और इनको लपेट कर सिगरेट बनाने वाली छोटी सी मशीन, जो इंग्लैंड की बनी हुई है। 3 विदेशी पाइप व तम्बाकू के पैकेट, सिगरेट जलाने वाले लाइटर भी मिले हैं।

उनके कमरे में अंग्रेजी व बंगला में हस्तलिखित 1683 पत्र भी मिले हैं। दो भारतीय और एक अमेरिकी हस्तलेखन विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है कि इन पत्रों में लिखावट 1935-36 की नेताजी की लिखाई से मेल खाती है। पूजा के सामानों में तीनमुखी व छहमुखी रुद्राक्ष की, स्फिटक व तुलसी की 28 मालाएं मिली हैं। गौमुखी कमंडल, आचमनी, शिवलिंग, शिवजी व मां काली के चित्र, मैहर की देवी का चित्र, चंदन की लकड़ियां, सिंदूर, आलता, शंख (जिसे कान के पास लाने पर वह गूंजता है) मिला है। गुमनामी बाबा के कमरे से 13 कमीजें, 4 पैंट, 31 बनियान, 31 चड्डी, 58 धोतियां, 3 वार्मर, 2 दस्ताने, 2 बरसाती कोट, 30 तौलिये, 1 जैकेट, 2 जोड़ी काले जूते, 1 जोड़ी लाल जूते, चेरी ब्लॉसम की पॉलिश के डिब्बे, जूता चमकाने की क्रीम, खड़ाऊं, बंदर टोपी, 7 गद्दे, राजस्थानी रजाई जिस पर रेशम की कढ़ाई है, चादर व तकिये आदि भी मिले हैं। कमरे से जो बर्तन व रसोई का सामान मिला है उसमें से कुछ विदेशों में निर्मित हैं, जो उनके लाइफस्टाइल को दर्शाता है। चूंकि वे होम्योपैथी के अच्छे जानकर थे, इसलिए इसकी व दूसरी तमाम दवाइयां भी मिली हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि गुमनामी बाबा अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे तो और कौन थे?

(लेख में विचार निजी हैं)

रोचक बात यह है कि 23 जनवरी को देश भर में जहां भी उनका जन्मदिन मनाया जाता था उसकी खबरों में से सुभाष चंद्र बोस की फोटो निकाल कर संग्रह की गई हैं। इसी बक्से से नेताजी की बचपन से मित्र रहीं और क्रांतिकारी संगठन की नेत्री सुश्री लीला रॉय, पंडित नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद और महात्मा गांधी के चित्र भी मिले हैं। उनके संगीत संग्रह में महिषासुरमर्दनी सोत की रिकॉर्डिंग, रवींद्र संगीत, नजरुल इस्लाम, श्यामा संगीत, केएल सहगल के रिकॉर्ड मिले हैं

तमाम मीडिया हाइप के बावजूद मोदी-शी बैठक से आशावाद तो उभरा लेकिन कुछ ठोस निकलता नहीं दिख रहा। दोनों नेताओं ने हालांकि सकारात्मक संकेत देने की कोशिश तो की है, लेकिन सुरक्षा, व्यापार और काफी समय से दोनों देशों के संबंधों में तनाव का कारण बने सीमा संबंधी विवाद को लेकर कुछ खास होता नहीं दिखा। अलबत्ता, दावे किए जा रहे हैं कि 'भारत और चीन के लिए मित्रता की मुद्रा में बने रहना ही मुफीद है' और यह संकेत देना भी ठीक है कि 'विश्व शांति के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग वक्त का तकाजा है' और इस मामले में तो दोनों पक्ष एकमत हैं ही।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक @Chellaney

अतीत, वर्तमान और भविष्य

वित्तीय समावेशन | अनिल गुप्ता

बहुत समय नहीं बीता जब केवल 35 भारतीयों के पास ही औपचारिक रूप से बैंक खाता हुआ करता था और उनमें से भी महज 8 ही औपचारिक ऋण की सुविधा लेते थे। ग्रामीण भारत की बुजुर्ग राजेश्वरी देवी जैसी अनगिनत महिलाओं को बैंक खाता खुलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कम से कम एक बैंक खाते के साथ वित्तीय समावेशन प्राप्त करना भारत में बड़ी चुनौती रही है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त, 2014 को शुरू किए जाने के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को उचित दूरी के भीतर किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था। 2025 तक भारत में बैंक खाता रखने वालों की तादाद बढ़ कर 90 हो गई, जो 2011 के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक है और 79 के विश्वव्यापी औसत से बेहतर प्रदर्शन है।

विश्व बैंक ने बताया कि भारत ने छह वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जिसमें अन्यथा 47 साल लगते। पीएमजेडीवाई के तहत 'मेरा खाता, भाग्य विधाता' बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता को सक्षम करने के लक्ष्य को दर्शाता है। जुलाई, 2025 तक 55.98 करोड़ खातों का आधार और 2.62 लाख करोड़ रुपये का लगातार बढ़ता जमा आधार, निम्न और मध्यम आय वर्ग (एलएमआई) को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने में इस जन आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। खास बात यह है कि 66.7 लाभार्थी ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं, जो दूरदराज क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने में पीएमजेडीवाई के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है। लगभग 55.8 पीएमजेडीवाई खाताधारक महिलाएं हैं, जो बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में मौजूद लैंगिक अंतर को देखते हुए एक और उपलब्धि है।

जुलाई, 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत लगभग 23.60 करोड़ लोगों ने कुल मिला कर नामांकन किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में कुल 51 करोड़ मिलियन नामांकन हुए। 7.6 करोड़ लोगों ने सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) योजना

में नामांकन किया। मार्च, 2025 तक वित्तविहीन लोगों को वित्त प्रदान करने की पहल के तहत बैंकों ने सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसायों को कुल 32.6 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ ऋण स्वीकृत किए। एमएससी के शोध से पता चलता है कि 67 महिलाओं और 64 पुरुषों ने मुख्य रूप से भविष्य के लिए बचत करने के लिए बैंक खाते खोले। बचत व्यवहार में बदलाव लोगों के लिए उन वित्तीय झटकों का प्रबंधन करने के लिए महत्त्वपूर्ण है जो एलएमआई परिवारों को गरीबी में धकेल देते हैं। पीएमजेडीवाई ने बचत को सक्षम किया, जबकि औपचारिक वित्तीय इतिहास के बिना लोगों को ऋण तक पहुंच प्रदान की। खाताधारक अब बचत पैटर्न दिखा सकते हैं, जो उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए पात्र बनाता है। जन धन ने जन समृद्धि के लिए मंच तैयार किया है, जहां उपयोगकर्ता उपयुक्त और किफायती सेवाओं के साथ अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। एमएससी का शोध दर्शाता है कि लोग अपने खातों का उपयोग एक या दो सेवाओं के लिए करते हैं। इस प्रकार, हमें प्रासंगिक समाधानों को संशोधित और/या विकसित करके जुड़ाव में सुधार करने के तरीके खोजने होंगे जो अनुरूप समाधान, स्पष्ट संचार, विश्वसनीय शिकायत प्रक्रियाओं और लचीले अंतिम ढांचे के साथ एलएमआई समूह की आकांक्षाओं संबोधित करते हैं।

भारत के फास्ट पेमेंट्स में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरने के कारण हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपार अवसरों को अनलॉक करने के लिए अधिक पीएमजेडीवाई खाताधारकों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अन्य संबंधित कार्यक्रमों के साथ तालमेल और स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय, वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए डिजिटल अंतर को पाटने में मदद कर सकता है। सच्चा वित्तीय समावेशन सिर्फ पहुंच से परे है; यह सही उत्पादों और सेवाओं, उच्च सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देने के बारे में है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए वित्तीय समावेशन की यात्रा कठिन है। पीएमजेडीवाई ने लाखों लोगों विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने और राजेश्वरी देवी जैसे लोगों के लिए अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए सशक्त बनाया है, जो कतार में सबसे आखिर में हैं।

(अनिल गुप्ता माइक्रोसेव कंसल्टिंग में पार्टनर हैं, और सहलेखक अभिषेक कटारिया माइक्रोसेव कंसल्टिंग में प्रबंधक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

नर-नारी | श्रीराम शर्मा आचार्य

काम का अर्थ विनोद, उल्लास और आनंद है। मैथुन को ही काम नहीं कहते। काम क्षेत्र की परिधि में वह भी एक बहुत ही छोटा और नगण्य सा माध्यम हो सकता है, पर वह कोई निरंतर की वस्तु तो है नहीं। यदा-कदा ही उसकी उपयोगिता होती है। इसलिए मैथुन को एक कोने पर रख कर उपेक्षणीय मान कर भी काम लाभ किया जाता है। स्नेह, सद्भाव, विनोद, उल्लास की उच्चस्तरीय अभिव्यक्तियां जिस परिधि में आती हैं, उसे आध्यात्मिक काम कह सकते हैं। नर-नारी के बीच व्यापक सद्भाव सहयोग की, संपर्क की स्थिति में ही व्यक्ति और समाज का विकास संभव है। उससे हानि रत्ती भर भी नहीं। स्मरण रखा जाए पाप या व्यभिचार का सृजन संपर्क से नहीं, दुर्बुद्धि से होता है। पुरुष डाक्टर नारी के प्रजनन अवयवों तक का आवश्यकतानुसार ऑपरेशन करते हैं। उसमें न पाप है, न अश्लील, न अनर्थ। रेलगाड़ी की भीड़ में नर-नारियों के शरीर चिपके रहते हैं। जहां पापवृत्ति न हो वहां शरीर का स्पर्श दूषित कैसे होगा? हम अपनी युवा पुत्री के शिर और पीठ पर स्नेह का हाथ फिराते हैं, तो पाप कहां लगता है। सान्निध्य पाप नहीं है। पाप तो अलग ही छूत की बीमारी है जो तस्वीरें देख कर भी चित्त को उद्विग्न कर सकने में समर्थ है। इलाज इस बीमारी का किया जाना चाहिए। हमारी कुत्सा का दंड बेचारी नारी को भुगतना पड़े, यह सरासर अन्याय है। इस अनीति को जब तक बरता जाता रहेगा, नारी की स्थिति दयनीय बनी रहेगी और इस पाप का फल व्यक्ति और समाज को असंख्य अभिशापों के रूप में बराबर भुगतना पड़ेगा। भगवान वह शुभ दिन जल्द लाए जब नर-नारी स्नेह सहयोग की तरह, मित्र और सखा की तरह एक दूसरे के पूरक बन कर सरल स्वाभाविक नागरिकता का आनंद लेते हुए जीवन यापन कर सकने की मनःस्थिति प्राप्त कर लें। हम विकारों को रोकें, सान्निध्य को नहीं। सान्निध्य रोक कर विकारों पर नियंत्रण पा सकना संभव नहीं। इसलिए हमें उन स्रोतों को बंद करना पड़ेगा जो विकारों और व्यभिचार भड़काने में उत्तरदायी हैं। अग्नि और सोम, प्राण और रयि, ऋण और धन विद्युत प्रवाहों का समन्वय इस सृष्टि के संचरण और उल्लास को अग्रगामी बनाता चला आ रहा है। नर-नारी का सौम्य संपर्क बढ़ा कर हमें खोना कुछ नहीं, पाना अपार है।

रीडर्स मेल

लड़कियों की शिक्षा जरूरी

हाल ही देश में दहेज के कारण हुई लड़कियों की मौतें चिंता का विषय हैं। आज लोग पढ़-लिख गए हैं, और उनका आधुनिकता की तरफ रुझान है तो दहेज के लालच में मौत/हत्याएं क्यों हो रही हैं? हमारे देश में माता-पिता लड़कियों की शादी को बहुत अहमियत देते हैं। इसके लिए बेटियों की नौकरी और पढ़ाई बीच में छुड़वाने से भी कतराते नहीं हैं। यह बहुत अजीब बात है कि बेटियों के मां-बाप ससुराल की सारी नाजायज मांगों को पूरा करते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें जमीन बेचनी पड़े या कर्ज तक लेना पड़े। पर बेटियों को पढ़ा-लिखा, आत्मनिर्भर बनाना उचित नहीं समझते हैं। माता-पिता को यह बात समझनी होगी कि लड़कियों को शोषण, अत्याचार और दहेज जैसी कुप्रथा से बचाने के लिए उन्हें पढ़ा-लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। साथ ही साथ बेटियों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाना भी जरूरी है ताकि वो ससुराल में प्रताड़ित हों तो अपनी जान से हाथ न धोने पाएं।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

समाचारपत्रों से विमुखता

वर्तमान में समाचारपत्र का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। मोबाइल के माध्यम से लोगों को कल सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसलिए समाचारपत्र अब कम लोग पढ़ रहे हैं, और नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा समाचारपत्र से तो विमुख ही होते जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह भी होती है कि अपने पसंदीदा खबर को लोग समाचारपत्र खरीद कर भले नहीं पढ़ें लेकिन उस न्यूज की कटिंग को डिजिटल फॉर्मेट में देख कर उतनी ही खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। वहीं समाचारपत्र बन रहे मोबाइल की स्थिति को देखें तो अब कल का इंतजार नहीं करना पड़ता है, लेकिन समाचारपत्र में जो जानकारी आपको सटीक, सारगर्भित, समुचित, सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मिलती रही है, वह मोबाइल के माध्यम से नहीं मिलती है। लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, और वह नहीं देख पाते हैं, जो आपको चाहिए, बल्कि जो कंपनियां चाहती हैं, वह आप देखते चले जाते हैं। सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वर्तमान पीढ़ी समाचारपत्र से विमुख न होकर पढ़ने की ओर प्रेरित हो।

डॉ. मिथिलेश कुमार, भागलपुर

जातिवाद पर कठोर प्रहार

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय शताब्दी समारोह में कहा है कि भारत बुद्ध की धरती है, और भारत एक शांतिपूर्ण देश है। आज विश्व में चारों तरफ आपसी टकराव और युद्ध का माहौल बना हुआ है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के वैचारिक शांति संदेश को समझाना होगा। इसी अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि बिस्मिल का सम्मान है, तो अशफाक खान का भी सम्मान है। मुसलमान को भी विश्वास दिलाया कि हिन्दू आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आक्रांताओं के नाम पर शहर और कस्बे न हों। इस अवसर पर उन्होंने जातिवाद पर कठोर प्रहार किया और देश सदियों से गुलाम रहा, इसका कारण इसे बताया। आरक्षण व्यवस्था को संघ का पूरा समर्थन होने की बात कही है। यह सभी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य संघ की देश के प्रति वर्तमान की प्रगतिशील वैचारिक प्रतिबद्धता दर्शाता है, और हम क्यों न विश्वास करें कि समय बदल गया है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/424/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 20, अंक 6762

आर.एन.आई. नं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936

चीन में नई मिठास

वर्षों बाद भारत और चीन के बीच एक तरह की अनुकूलता का माहौल स्वागतयोग्य है। चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर आमने-सामने की वार्ता हुई है, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने माना है कि हाथी और ड्रैगन का साथ-साथ चलना जरूरी है। खासतौर तौर पर चीन की ओर से यह बात समझाने की कोशिश हुई है कि दोनों देश परस्पर प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि विकास में साझीदार हैं। वास्तव में, भारत की चीन के प्रति सद्भावना सदैव रही है, पर चीन की ओर से ही नाना प्रकार की आक्रामकता का दुखद इतिहास रहा है। बीजिंग में खुशनुमा बातचीत के बावजूद इस आक्रामकता को भुलाया नहीं जा सकता। हां, जिनपिंग के अच्छे उद्गार उम्मीद जरूर जगाते हैं कि ड्रैगन अब हाथी के महत्व को नए सिरे से स्वीकारना चाहता है। जिनपिंग की यह भावना स्वागतयोग्य है कि 'चीन और भारत, दो सबसे सभ्य देश हैं। हम दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। हमारा दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है।'

इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के 2 अरब, 80 करोड़ लोग इन दोनों देशों में ही रहते हैं और दोनों के बीच शांतिपूर्ण संबंध जरूरी है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बहुत ज्यादा है और दोनों का एक-दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। चीन की तेज तरक्की काबिलेगौर है और विश्व स्तर पर भारत को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के बीच मतभेद रह सकते हैं, मगर उन्हें विवाद में बदलने से अवश्य रोका जा सकता है। यहां विवाद को बढ़ने से रोकने व समाधान की जिम्मेदारी चीन पर ज्यादा है, क्योंकि महाशक्ति बनने की उसकी रणनीति व महत्वाकांक्षा भारत की तुलना में बहुत विस्तृत है। किन्हीं अर्थों में भारत महत्वाकांक्षी राष्ट्र नहीं है और न उसे साम्राज्यवाद के प्रति कोई लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता के दौरान उचित ही कहा है कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगे हाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि पिछले साल फौज वापसी प्रक्रिया के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता है। वाकई, दोनों देशों के बीच किसी तरह का सामरिक विवाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चीन ने कुछ देशों के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझाया है, ठीक वैसे ही भारत के साथ भी उसे करना चाहिए। वैसे, चीन सीमा विवाद के महत्व को जानता है, इसलिए वह दोनों देशों के संबंधों को इस विवाद तक समेटकर नहीं देखना चाहता।

चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना है कि बदलती दुनिया में हाथी और ड्रैगन का साथ-साथ चलना जरूरी है।

कोई दोराय नहीं कि विगत एक वर्ष में भारत-चीन संबंधों में सुधार आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। पिछले वर्ष 2024 में कजान में दोनों शीर्ष नेता मिले थे और उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में बहुत सुधार आया है। ऐसी मुलाकातें फायदेमंद होती ही हैं। अब दोनों देशों को और आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि दोनों फायदे में रहें। बीजिंग में दोनों नेता मिलकर दुनिया को जो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने दे दिया है। अब आगे हकीकत में रिश्तों को मजबूत करने के लिए ठोस काम की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चीन दौरे से हम उम्मीद रख सकते हैं। बेशक, 31 अगस्त को तियानजिन में 'शंघाई सहयोग संगठन' के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात एक खुशनुमा वर्तमान है, जहां से हम नए भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 01 सितम्बर, 1950

कृषि-वैज्ञानिकों का कर्त्तव्य

भारतीय कृषि अनुसंधानशाला के स्नातकोत्तर छात्रों के समक्ष भाषण करते हुए राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। खाद्य के संबंध में देश के स्वावलम्बी होने पर तो प्रायः सभी का जोर है, परन्तु आम झुकाव प्रचार और पश्चिमी उपायों को अपनाने पर ही मालूम पड़ता है। पश्चिम का प्रभाव हम पर कुछ ऐसा छाया हुआ है कि हर बात में उसकी अंधी नकल में ही मानो हम अपना गौरव और विस्तार मानते हैं। जो हमारे यहां का मुख्य और गौरवपूर्ण धंधा रहा है, उसके बारे में भी हम पश्चिम की ही नकल करने के इच्छुक प्रतीत होते हैं, जिसका एक कारण शायद यह भी है कि और विषयों की तरह इस विषय की उच्च शिक्षा भी हम पश्चिमी देशों में ही प्राप्त करते हैं और जो वहां सिखाया जाये, उसी के अनुसार काम कर सकते हैं। यह सोचने और परीक्षण करने की शायद जरूरत नहीं समझी जाती, न इच्छा ही होती है कि हमारे यहां की स्थितियों में वे तरीके उसी रूप में चलने चाहिए या उससे भिन्न रूप में और यह कि हमारे यहां जो तरीके प्रचलित हैं, उनमें क्या खराबी है तथा क्या उन्हीं में कुछ ऐसे फेरबदल नहीं किये जा सकते कि उनकी खूबी बनी रहे और कमियां जो हों वे पूरी कर ली जायें। राजेन्द्र बाबू ने परम्परा के विरुद्ध इसी दिशा में सोचने और करने की कृषि-वैज्ञानिकों को सलाह दी है। इसलिए उनके कहे का महत्त्व है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजेन्द्र बाबू ने किसानों के प्रति हीनता के बजाय सहानुभूति और सद्भावना का रुख रखने को कहा है, जो इस दिशा में कार्य करने वालों के लिए निश्चय ही प्राथमिक आवश्यकता है। सहानुभूति और सद्भावना की बात करके वह कृषि वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं कि भारतीय किसान जिन तरीकों से खेती कर रहे हैं, उनका वे पूर्ण रूप से अध्ययन करें और अपने वैज्ञानिक अनुभवों का समावेश करके उन्हें अधिक उपयोगी बनायें। पश्चिम की चकाचौंध में हम भारतीय तरीकों को कितना ही पिछड़ा हुआ मानें, राजेन्द्र बाबू की बात वजनदार है कि सदियों से भारत के किसान उन्हें अपनाये हुए हैं और समयानुसार सुधार उनमें करते रहे हैं। यही नहीं बल्कि उनके अनुसार, उनमें से बहुतों का आधार वैज्ञानिक है और नई समस्याएं पैदा करने वाले आधुनिकतम तरीकों के बजाय संशोधित पुराने तरीकों की बात किसान के गले जल्दी उतरेगी।

रुपया को नया तेवर देने का दौर आया

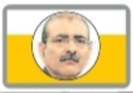

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

भारत, चीन और रूस जिस तरह एक-दूसरे से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें ब्रिक्स देशों की वैकल्पिक मुद्रा की संभावना से इनकार करना आसान नहीं होगा।

कभी-कभी मुसीबत भी वरदान साबित होती है। भारत के आर्थिक-राजनीतिक इतिहास में 1991 का विदेशी मुद्रा संकट ऐसी ही एक मुसीबत थी, जिसके दबाव में तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों का वह ऐतिहासिक सिलसिला शुरू किया, जिसने उद्योग-व्यापार ही नहीं, पूरे देश की तस्वीर बदलकर रख दी।

इसे अभी याद करने का एकमात्र मकसद यह है कि कहीं हम एक बार फिर ऐसी ही मुसीबत से आंखें चार तो नहीं कर रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ-मार से रुपया लगातार दबाव महसूस कर रहा है। यहां तक कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट रुपये के इस हाल पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। एक तरफ उनका कहना है, भारत और अमेरिका को आखिरकार साथ आना ही होगा, मगर दूसरी तरफ यह पूछने पर कि भारत अगर अपनी मुद्रा (रुपया) को ही दूसरे देशों से व्यापार के लिए रिजर्व करेंसी की तरह इस्तेमाल करने लगे, तब क्या होगा, तो अमेरिकी वित्त मंत्री ने इसे मजाक में उड़ा देना ही सही समझा।

हालांकि, यह सवाल बेवजह नहीं था। अमेरिकी टैरिफ के चक्कर में भारत के अनेक उद्योग और व्यापार परेशानी झेल रहे हैं। तिरुपुर, सूरत, लुधियाना और जयपुर जैसे अनेक औद्योगिक शहरों में बड़ी आबादी के कारोबार और रोजगार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शेयर बाजार का हाल दिखा रहा है कि चिंता गहरा रही है। अनुमान है कि टैरिफ की वजह से भारत के कुल निर्यात में करीब 4.5 हजार करोड़ डॉलर की गिरावट आ सकती है, जो अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि भारत के कुल निर्यात का करीब 23 फीसदी हिस्सा अमेरिका जाता है। जेफरीज के क्रिस वुड ने भी अनुमान लगाया है कि टैरिफ की वजह से भारत को 55 से 60 अरब डॉलर का झटका लग सकता है और इसकी तगड़ी चोट बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि रोजगारपरक छोटे व मझोले उद्योगों को भी लगेगी।

मगर यह मानने वालों का भी एक बड़ा तबका है, जिन्हें लगता है कि यह वक्त आपदा में अवसर तलाशने का है, और ऐसा हो गया, तो न सिर्फ यह मुसीबत टल सकती है, बल्कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी मजबूत होकर उभर सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा रास्ता तो यही दिखाया जाता है कि भारत अमेरिका को खुश करने की चिंता त्यागकर अपने उत्पादों के लिए दुनिया के दूसरे बाजारों में जगह बनाने की कोशिशें तेज कर दे। ऐसा हो भी रहा है। भारत ने दुनिया के 40 देशों में अपने निर्यातकों के लिए बाजार बढ़ाने को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इन देशों में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, मेक्सिको, रूस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।

इसके साथ ही एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या भारत को अब अनेक देशों के साथ अपना व्यापार डॉलर के बजाय रुपये में करना चाहिए? इसी सवाल का एक अन्य स्वरूप यह है कि क्या ब्रिक्स देशों को अपनी मुद्रा बना लेनी चाहिए, जो डॉलर की तरह एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व करेंसी बने और मुद्रा बाजार में अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे सके? यह प्रस्ताव कुछ पुराना है और इस पर राष्ट्रपति ट्रंप काफी तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि, चीन, रूस और भारत जिस तरह एक-दूसरे से बातचीत बढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसी मुद्रा की संभावना से इनकार करना आसान नहीं होगा। मगर इन तीनों देशों में एक स्थायी गठबंधन बन सके, इसकी राह में शक-शुबहे की कई ऐतिहासिक दीवारें खड़ी हैं, और आगे भी इनके बीच मित्रवत संबंध बरकरार रह पाएंगे, इस पर यकीन करना आसान नहीं है, खासकर भारत और चीन के बीच।

मगर इसके समानांतर यह गुंजाइश लगातार बनी हुई है कि भारत जिन देशों से व्यापार कर रहा है या जिनसे व्यापार बढ़ा रहा है, उनके साथ लेन-देन में रुपये का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी हो रहा है, क्योंकि डॉलर के उतार-चढ़ाव से दोनों ही पक्षों को समय-समय पर फायदा और नुकसान होता रहता है। तो क्या भारत हालात को पलटने की क्षमता रखता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने की हिम्मत करेगी? जवाब में सबसे बड़ा तर्क यही है कि जब सामने बड़ी मुसीबत हो, तब उससे निपटने के लिए उतने ही साहस का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है।

निश्चय ही डॉलर, पाउंड या यूरो के मुकाबले रुपये की कीमत चिंताजनक दिख रही है, मगर इस बात से हिम्मत भी मिलनी चाहिए कि पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का रुपया काफी मजबूत स्थिति में है। एक भारतीय रुपये की कीमत श्रीलंका में 3.44 रुपये, नेपाल में 1.60 रुपये, बांग्लादेश में 1.39 टका, पाकिस्तान में 3.22 रुपये होती है। थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में यही रुपया वियतनाम में 300 वियतनामी डोंग, इंडोनेशिया में 184 रुपिया, कंबोडिया में करीब 44 रिएल का हो जाता है।

इन सभी के मुकाबले देखें, तो भारतीय रुपया काफी मजबूत स्थिति में है। लिहाजा दो देशों के बीच अपनी मुद्रा में व्यापार होने लगे, तो फिर उन पर डॉलर के उतार-चढ़ाव का उतना असर भी नहीं पड़ेगा। ट्रंप के फैसलों की अनिश्चितता से परेशान बहुत से देश और व्यापारी ऐसे विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में, अगर भारत कई देशों से अपनी मुद्रा में व्यापार करने लगे, तो हो सकता है कि अनेक अन्य छोटे देश भी अपने व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करें या कम से कम इसकी कीमत का संदर्भ के लिए इस्तेमाल करें।

भारत के पास इसका अनुभव भी है। परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर जब अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के समय और अभी हाल में रूस पर पाबंदी के बाद इन देशों से भारत का लेन-देन अपनी मुद्रा में या सामान के बदले सामान के सौदों में हो चुका है। उस अनुभव का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीएसटी में भारी कटौती का एलान अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी, टैरिफ का जितना खराब असर हो सकता था, उसकी धार पहले ही काफी कुंद की जा चुकी है। लिहाजा, अभी हमारे पास मौका है और हालात भी अनुकूल हैं। अगर सब कुछ सही रहा, तो यहां से भारत के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारतीय समाज की तरक्की पर दहेज हत्याओं का दाग

कमलेश जैन | वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

भारत में, खासकर हिंदू विवाह व्यवस्था में दहेज अत्यंत ही पुरानी और लज्जास्पद बीमारी है, जिसके उन्मूलन का प्रयास करते हुए सरकार को लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं। गौर कीजिए, साल 1961 में ही दहेज निषेध अधिनियम बना था।

दरअसल, समय के साथ लोगों के जीवन में जैसे-जैसे पैसे आते गए, वैसे-वैसे ही दहेज उत्पीड़न के मामले भी बढ़ते चले गए। इस प्रताड़ना के तरीके भी बदले, बल्कि वीभत्स होते गए। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की हत्या इसका ज्वलंत उदाहरण है। खबरों के मुताबिक, निक्की के अमीर पिता ने स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल, गृहस्थी के लिए जरूरी तमाम आधुनिक सामान के साथ नगद रकम देकर बेटी का धूमधाम से विवाह किया था। ऊपर से निक्की ब्यूटी पॉर्लर चलाकर भी कमा ही रही थी। मगर निक्की के पति का लोभ कभी कम नहीं हुआ। 36 लाख रुपये और मर्सिडीज की मांग न पूरी होने पर उसने न सिर्फ निक्की को मारा-पीटा, बल्कि उस पर ज्वलनशील पदार्थ जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस कृत्य को अंजाम देने में निक्की की सास भी भागीदार रही, जिसे उसके छह वर्षीय बेटे ने भी देखा।

यूरोप या पश्चिम के देशों में विवाह या 'लिव-इन रिलेशनशिप' के पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। क्या अपने यहां भी ऐसा होना चाहिए?

ऐसी हत्याओं की संख्या प्रतिवर्ष हजारों में है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 के अंत तक अदालतों में 60,577 मुकदमे लंबित थे, जबकि उस साल 6,516 महिलाएं दहेज के लिए जान गंवा बैठीं। दरअसल, मुकदमों के फैसलों में अनावश्यक देरी ऐसी लापरवाही है, जो अपराधियों को फलने-फूलने के मौके देती है। कानून के अनुसार, दहेज का अर्थ है, कोई संपत्ति या कीमती चीज, जो विवाह के उपलक्ष्य में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती हो। इसका संबंध मुस्लिम विवाह कानून की 'मेहर' से नहीं है। वहां शरीयत कानून लागू होता है।

दहेज कानून का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें दहेज लेना और देना, दोनों ही अपराध है, जिसकी सजा कम से कम पांच साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना होगा। इस कानून की धारा-4 के अनुसार, दहेज मांगने पर परिजनों के लिए कम से कम छह महीने की जेल का प्रावधान है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जुर्माने की राशि न्यूनतम 10 हजार तय की गई है। समय के साथ-साथ दहेज की मांग, मात्रा और आकार-प्रकार बढ़ता गया है। मुझे याद है कि 1980 में बिहार में एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें एक साइकिल के लिए दुल्हन को स्टोव से जला दिया गया था। धीरे-धीरे मांग और प्रताड़ना बढ़ती गई। आज यह लाखों-करोड़ों में पहुंच चुकी है।

दरअसल, इस आपराधिक कुकृत्य पर रोक न लगते देख भारतीय दंड संहिता में धारा 498-ए लानी पड़ी, जिसमें दुल्हन के उत्पीड़न पर तीन साल तक कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया। शुरू में इस कानून के तहत एफआईआर होते ही, उसमें दर्ज तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। मगर जब झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे, तो तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई।

सवाल यह है कि हमारे देश में यह अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है? कानून और अदालतों के पास इसका इलाज क्यों नहीं है? यूरोप या पश्चिम के देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? असल में, वहां विवाह या 'लिव-इन रिलेशनशिप' के पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें तमाम खर्चों और उपहारों की एक सूची बनाई जाती है, जिसको कानूनी दस्तावेज की तरह सुरक्षित रखा जाता है। इसमें किसी भी शर्त को तोड़ने को अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। और इसके आधार पर अलग हुआ जा सकता है, उपहारों का बंटवारा हो जाता है। लोग स्वेच्छा से बिना किसी द्वेष-दुश्मनी के अलग हो जाते हैं।

हमारे यहां दहेज-तलाक का मामला हो या कोई और मुकदमा- वह वर्षों तक चलता रहता है, मानो कोई खेल आराम-आराम से खेला जा रहा हो। पति-पत्नी और उनके परिवार की जिंदगी शतरंज की बाजी बन जाती है। समाज का लालच, अदालतों की सुस्ती, न्यायपालिका की आरामपसंदी दरअसल मुकदमों को सुलझाना नहीं चाहतीं। इसलिए न कानून का भय स्थापित हो पा रहा और न इस कुरीति पर प्रभावी रोक लग पा रही है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अर्जुन को क्यों बताई गीता

एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, कृष्ण ने अर्जुन को ही *गीता* क्यों बताई? उनके पास युधिष्ठिर थे, जो धर्मराज कहलाते थे, *गीता* उनको कहीं अधिक समझ में आ सकती थी। अर्जुन तो योद्धा थे, तथाकथित अर्थों में वह अधार्मिक भी थे, जो धर्म पर इतने सवाल उठा रहे थे। लड़ने के लिए भी राजी नहीं थे। फिर, कृष्ण ने जब *गीता* का ज्ञान दिया, तब श्रोताओं में भी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। क्यों?

ऐसे सवालों के जवाब ओशो ही दे सकते हैं। उनसे ये सवाल पूछे गए, तब उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तथाकथित धार्मिक आदमी हैं। वह रूढ़िग्रस्त धार्मिक आदमी की प्रतिमा हैं। धार्मिक आदमी दो तरह के होते हैं। एक, उधार धार्मिक होते हैं, यानी जिनका धर्म अतीत की उधारी से आता है। और दूसरे धार्मिक आदमी वे होते हैं, जिनका धर्म उनकी आंतरिक क्रांति से आता है। जैसे, पंडित पुरोहित धर्म का पालन करने वाले होते हैं। जो कुछ शास्त्रों में बताया गया है, उसका विधिवत पालन करना-कराना उनका काम होता है। उनसे कुछ नया और क्रांतिकारी घटने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनमें वह आग नहीं होती। धर्मराज के मन में कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वहां क्रांति भी पैदा नहीं हो सकती थी।

अर्जुन आंतरिक क्रांति के द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। धार्मिक हैं नहीं, लेकिन क्रांति के द्वार पर खड़े हुए हैं। वह उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिससे धर्म पैदा हो सकता है। अर्जुन बहुत प्रामाणिक मनुष्य हैं। उनकी प्रामाणिकता इसमें है कि उन्हें चिंता है, उनके पास प्रश्न हैं। जो स्थिति है, उसमें वह राजी नहीं हो पा रहे हैं। उनकी यही बेचैनी, यही पीड़ा उनका विकास बनती है। इसलिए अर्जुन के विषाद को 'विषाद योग' कहा गया। लंबे प्रश्न-उत्तर के बाद अंततः अर्जुन ज्ञान को उपलब्ध हुए। विषाद भी योग है, क्योंकि विषाद आनंद के लिए जन्मने की प्रक्रिया है।

इस युद्ध से युधिष्ठिर को पीड़ा नहीं हुई। युधिष्ठिर बिलकुल राजी हैं महाभारत के युद्ध में; और एक अर्जुन हैं, जो न अधार्मिक होने से राजी हैं, न तथाकथित धर्म से राजी हैं, वह चिंतित हैं। धर्म का जन्म ही गहन सवालों से होता है। जो हो रहा है, वह ऐसा क्यों हो रहा है, यह सवाल मन में आना चाहिए? युद्ध की आखिरी घड़ी में अर्जुन के मन को संदेह ने पकड़ लिया है। वस्तुतः जब भी आपको कोई कर्म करने का निर्णय लेना होता है, तब आप सभी अर्जुन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से ही बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन बार-बार प्रश्न उठा रहे हैं और कृष्ण बार-बार उत्तर दिए जा रहे हैं। इसीलिए तो *गीता* इतनी लंबी हुई। संदेह से धर्म पैदा हो सकता है, विश्वास से नहीं।

अर्जुन बहुत प्रामाणिक मनुष्य हैं। उन्हें चिंता है, उनके पास प्रश्न हैं। जो स्थिति है, उसमें वह राजी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए अर्जुन के विषाद को 'विषाद योग' कहा गया।

अमृत साधना

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

स्वाधीनता के बाद से सार्वजनिक उद्यम आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश का शक्तिशाली माध्यम रहे हैं। साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय लक्ष्य पाने में इन उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

अनुलोम-विलोम
विपक्ष की प्रासंगिकता

विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती जनता

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक सुझाव पेश करता है। यदि विपक्ष मजबूत और जिम्मेदार हो, तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनता है। मगर आज की राजनीति में यह देखने को मिल रहा है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय कुतर्कों और निरर्थक आलोचनाओं में उलझकर स्वयं ही महत्वहीन होता जा रहा है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। मगर आजकल विपक्ष के कई नेता तथ्यों को पुष्ट किए बिना केवल सत्ता पक्ष की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। वे हरेक मुद्दे पर नकारात्मक रुख अपनाते हैं। जब विपक्ष अपनी राजनीति को केवल विरोध तक सीमित कर देता है, तो जनता का विश्वास उस पर से उठने लगता है। वह सरकार की आलोचना तो करता है, लेकिन जनता को यह भरोसा नहीं दिला पाता कि उसके पास कोई ठोस विकल्प है। ऐसे में, जब जनता को कोई विकल्प नजर नहीं आता, तो स्वाभाविक ही विपक्ष से उसकी दूरी बनने लगती है। लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है, जब विपक्ष जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। केवल सत्ता पाने की लालसा या आलोचना की राजनीति करने से वह मतदाताओं और व्यापक जनता का विश्वास कभी नहीं जीत पाएगा।

समराज चौहान, टिप्पणीकार

प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित शब्द कहे जाने का मामला बेहद गंभीर है। यह बताता है कि विपक्ष अब कितना हताश हो गया है। इस हताशा में उसे यह भान भी नहीं कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि विरोध के स्वर अमर्यादित न हों। दिक्कत यह है कि आज नेताओं की आपसी कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि उनमें संवाद खत्म हो गया है। वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। ताजा घटनाक्रम इसी सोच का नतीजा है। इस तरह की टिप्पणी जनता में विपक्ष की स्वीकार्यता को घटाने का काम करेगी। निश्चय ही सत्ता पक्ष की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन यह सार्थक हो, न कि निरर्थक। अगर इसी तरह विपक्षी दलों की ओर से अपमानजनक बयान आते रहेंगे, तो जो थोड़े बहुत मतदाता उससे जुड़े हैं, वे भी छिटक सकते हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

जमीन पर दिख रही विपक्षी एकजुटता

विपक्षी दलों के अप्रासंगिक हो जाने की बहस कोई नई नहीं है। जब भी विपक्ष सक्रियता से उभरता दिखता है और सत्ता पक्ष को मजबूती से घेरता प्रतीत होता है, तब ऐसी बहसें प्रायोजित की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि यह माहौल बने कि विपक्ष मैदान में है ही नहीं या वह तो सोया हुआ है और बिल्कुल बिखरा हुआ है। जबकि, हकीकत यह है कि आज का विपक्ष पहले से ही कहीं अधिक मजबूती से एकजुट है और सरकार का सीधा मुकाबला कर रहा है।

अब बिहार की यात्रा का ही विश्लेषण कीजिए। वहां जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, वह लगातार सुर्खियों में हैं। उनको न सिर्फ लगातार कवरेज मिल रही, बल्कि लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। यात्रा के दौरान जनता की उमड़ती भीड़ से तो कम से कम यही संकेत मिल रहा है। इंडिया टुडे और सी वोटर के हालिया सर्वे में भी विपक्ष के नेता के रूप में ज्यादातर लोगों ने राहुल गांधी के काम को सराहा है और उन्हें 'इंडिया' ब्लॉक में अपनी पहली पसंद बताया है। मुमकिन है कि इस यात्रा से विपक्ष के पक्ष में बनते माहौल पर पानी डालने के लिए ही कथित गाली प्रकरण उठाया जा रहा हो, ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटाया जा सके। नहीं तो यह कोई ऐसा मसला नहीं कि जिसके लिए बिहार से लेकर देश की राजधानी तक आक्रामक विरोध-प्रदर्शन किए जाएं।

बात दरअसल यही है कि विपक्ष अब अधिक आक्रामकता से जवाब देने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने से उसमें जो जान आई है, वह अब तक बनी हुई है। यह सही है कि कभी-कभी विपक्षी दलों में मतभेद की खबरें भी आती हैं, लेकिन उनकी आपसी नाराजगी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती और उनमें फिर से एकता दिखने लगती है। यही कारण है कि सभी विपक्षी दल अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और सीधे-सीधे सत्ता पक्ष से मुकाबला कर रहे हैं। जब विपक्ष में इतना जोश हो, तो भला उसे निष्क्रिय कैसे कह सकते हैं! यह तो उसे जबरिया कमतर आंकना होगा। अलबत्ता, मेरा तो यही मानना है कि वह कहीं अधिक सक्रिय है और उसकी यह सक्रियता चुनाव में जरूर दिखेगी, खास तौर से बिहार विधानसभा चुनाव में, जो इस बार काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसमें मुकाबला दो गठबंधनों के बीच आमने-सामने का होगा। ऐसे में, विपक्ष को कमजोर और महत्वहीन बताने की बहस कोई मायने नहीं रखती। जनता ऐसी बहसों को बहुत अहमियत देती नहीं दिख रही।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

चिंतन

चीन से दोस्ती तो ठीक सतर्क रहना भी जरूरी

चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। ये विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों साथ आते हैं तो दोनों देशों का ही नहीं बल्कि 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा। आज चीन के शहर बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का सार यही है। सात साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत-चीन के संबंध खराब हो गए थे। गलवान झड़प के बाद मोदी पहली बार चीन पहुंचे हैं। हालांकि दोनों नेताओं में रूस में मुलाकात हो चुकी है। वैसे भी गलवान के तनाव और अब के हालात में बहुत अंतर है। इस अंतर का कारण हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सबसे पहले चीन को निशाने पर लिया था। उस पर एक के बाद एक टैरिफ थोपे गए। हालांकि बाद में वो चीन को लेकर नरम पड़ गए और भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपनी सनक के चलते कब क्या फैसला लेंगे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि मिलकर उनसे मुकाबला किया जाए। यह पहला मौका नहीं है जब भारत और चीन साथ आए हो। कभी 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा लगता था, लेकिन 1962 के युद्ध ने रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। भारत और चीन के रिश्तों की शुरुआत 1938 में हुई थी। उस समय चीन जापान के हमलों से परेशान था। भारत ने इंसानियत दिखाते हुए चीन की मदद के लिए एक मेडिकल टीम भेजी। इस टीम में पांच भारतीय डॉक्टर थे, जिनमें से एक थे डॉ. द्वारकानाथ कोटनीस। डॉ. कोटनीस ने चीन के लोगों की सेवा करने का फैसला किया और वहीं रुक गए। भारत और चीन ने आजादी के बाद अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। दोनों देशों ने एक समझौता किया। यह समझौता 29 अप्रैल, 1954 को हुआ था लेकिन यह समझौता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1959 में जब भारत ने चीन से भागे दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल देना माना। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ने लगा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर झोउ एनलाई ने कई बार मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 20 अक्टूबर, 1962 को चीन ने भारतीय सीमा पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने भारत के भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया। साल 2020 में लद्दाख के अक्साई चिन में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत ने चीन के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया था। फ्लाइट सर्विस भी रोक दी गई थी। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा करना मुश्किल हो गया था। भारत के लिए परेशानी का एक कारण चीन द्वारा बार-बार पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना भी है। वो पाक का समर्थन करके आतंकवाद के समर्थन में खड़ा हो जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद जिनपिंग का यह कहना कि ड्रैगन (चीन) और हाथी (भारत) को साथ आना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और चीन-भारत की दोस्ती समय की मांग भी है, लेकिन चीन की विस्तारवादी सोच के चलते भारत को हमेशा सतर्क भी रहना होगा।

टैरिफ संकट
विकेश कुमार बडोला

जल्द निकालना होगा टैरिफ का तोड़

भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं में आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, इत्यादि सम्मिलित हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन में नियुक्त औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सम्मुख आगामी समय चुनौतियों से पूर्ण होगा। जब तक भारतीय शासन द्वारा अमेरिका को विभिन्न वस्तुयें निर्यात करने के माध्यम से वैश्विक बाजार में टिके हुए निर्यातकों को बड़े व नवोन्मेषी राहत पैकेज नहीं मिल जाते अथवा अमेरिका के साथ वार्ता करके अतिरिक्त शुल्क के निर्णय को निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता, तब तक इनके स्तर पर देशी-विदेशी व्यापार मंद होता रहेगा। हालांकि भारतीय वाणिज्य विभाग निर्यातकों की सहायता के लिए विविध आयामी व्यापार नीति पर कार्य कर रहा है।

अंततः भारत-अमेरिका की आर्थिक शत्रुता बढ़ाने वाला बड़ा निर्णय ट्रंप ने ले ही लिया। गत 28 अगस्त से अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय उत्पादों पर कुल पचास प्रतिशत शुल्क लगने लगेगा। भारत में तो नहीं किंतु अमेरिका में बढ़े हुए शुल्क के शासकीय निर्णय पर पक्ष-विपक्ष के राजनेता तथा उनसे संबद्ध विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दो समूह बन गये हैं। एक समूह भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को अनुचित मान रहा है, तो दूसरा ट्रंप के निर्णय का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सकारात्मक हैं। वे आशान्वित हैं कि अंततः अमेरिका व भारत के मध्य अर्थव्यवस्था की अनुकूल स्थितियां बनेंगी। उनके अनुसार एकपक्षीय टैरिफ व कुछ अनावश्यक वक्तव्यों के बाद भी दोनों देशों के मध्य वार्ता की राह बंद नहीं हुई है। कुछ अन्य प्रभावशाली पदाधिकारी भी बारंबार कह रहे हैं कि यदि भारत पर पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीद के कारण लगा है तो फिर चीन पर बढ़ा हुआ टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि वो तो भारत की तुलना में रूस से अधिक तेल आयात कर रहा है।

इस आपत्ति के आलोक में विचार करें तो यही ज्ञात होता है कि ट्रंप जो हैं वे मोदी के साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता के कारण यही चाहते थे कि भारत के साथ प्रस्तावित अमेरिका के अनेक क्षेत्रों, विशेषकर व्यापार से संबंधित समझौतों पर भारत वैश्विक भूराजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्यों पर विचार किये बिना ही सहमति के साथ हस्ताक्षर कर दे। भारत ने ऐसा नहीं किया और अमेरिकी टैरिफ के चक्रव्यूह में फंस गया। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं में आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, इत्यादि सम्मिलित हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन में नियुक्त औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सम्मुख आगामी समय चुनौतियों से पूर्ण होगा। जब तक भारतीय शासन द्वारा अमेरिका को विभिन्न वस्तुयें निर्यात करने के माध्यम से वैश्विक बाजार में टिके हुए निर्यातकों को बड़े व नवोन्मेषी राहत पैकेज नहीं मिल जाते अथवा अमेरिका के साथ वार्ता करके अतिरिक्त शुल्क के निर्णय को निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता, तब तक इनके स्तर पर देशी-विदेशी व्यापार मंद होता रहेगा। हालांकि भारतीय वाणिज्य विभाग निर्यातकों की सहायता के लिए विविध आयामी व्यापार नीति पर कार्य कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर निर्यातकों हेतु नकदी की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मूलतः अमेरिका में वस्तुयें भेजने वाले निर्यातकों को शीघ्रातिशीघ्र सहायता उपाय लागू करने का भरोसा दिया है। शासन पहले से चली आ रही योजनाओं को पुनर्जीवित करने व निर्यात संवर्द्धन अभियान को भी शीघ्र लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री जापान, चीन की यात्रा पर हैं। वे इस समयावधि में प्रमुख रूप से भारत के उन आर्थिक-व्यापारिक क्षेत्रों के लिए ही नये विकल्प ढूंढने को प्राथमिकता देंगे, जिन्हें अमेरिकी टैरिफ के बाद मंदी का सामना करना पड़ेगा। टैरिफ संकट से निकलने का प्रत्यक्ष एवं आसान उपाय तो यही है कि भारत टैरिफ की चिंताओं व समस्याओं के संबंध में अमेरिका से निरंतर वार्ता करता रहे। अमेरिकी वित्त मंत्री सहित भारत हितैषी कुछ नेताओं द्वारा इस संदर्भ में सकारात्मक

वक्तव्य भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं गुप्त रूप से यही इंगित कर रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटते ही भारत-अमेरिका के मध्य टैरिफ संकट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

टैरिफ व्यूह से निकलने के इन तात्कालिक उपायों, आशाओं एवं कार्यों के अतिरिक्त भारत को अपनी भावी आर्थिक स्थितियों को अमेरिका या किसी एक बड़े देश पर आश्रित करने की तुलना में आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी के अर्थबल द्वारा साधना होगा। स्वदेशी अर्थव्यवस्था को कार्यबल देकर भारत टैरिफ की समस्याओं से तात्कालिक मुक्ति पा सकता है। पारंपरिक रूप से मांग व उपभोग आधारित रही अपनी अर्थव्यवस्था को भारत एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग के चरण तक आर्थिक वृद्धि का आधार बना सकता है। इसके लिए भारतीय बाजारों को वस्तु के कम मूल्य से लेकर गुणवत्ता तक का तो ध्यान रखना ही होगा, साथ ही बाजारीकरण के पुराने ढर्रे और ऑनलाइन आपूर्ति शृंखला का सामंजस्य भी बनाये रखना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण उद्योगों में निर्मित होने वाले यांत्रिक उत्पादों में लगने वाले छोटे व सहायक उपकरणों हेतु मेक इन इंडिया अभियान को स्टार्ट अप से जोड़कर परिणोन्मुखी व लाभोन्मुखी बनाना होगा। अमेरिका को निर्यात होने वाले हीरे-जवाहरात, वस्त्र, शिल्पकारी की वस्तुओं, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों व अन्य उत्पाद सामग्रियों के लिए मांग आधारित स्वदेशी व विदेशी, दोनों बाजारों में मूल्य को प्रतिक्षण प्रतिस्पर्द्धी व लचीला रखना होगा। मूल्यह्रास की प्रतिस्पर्द्धा में बने रहकर होने वाली आर्थिक हानि को वस्तुओं व सामग्रियों की मांग में पुनरावृत्ति करके कम करना होगा।

अमेरिका को छोड़ जिन अन्य देशों के साथ भारत का आयात-निर्यात दहाई के प्रतिशत में है, उनके हाई परचेजिंग उपभोक्ताओं में भारतीय उत्पादों व सेवाओं के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न करने की दिशा में कार्य करना होगा। अभी ब्रिक्स के दो सदस्य देशों रूस और ब्राजील को भी भारत के निर्यात खरीदार के रूप में स्थापित करने की चुनौती सामने है। विश्व में जनसंख्या में शीर्ष के तीन देशों में तो अमेरिका, चीन समेत स्वयं भारत प्रथम स्थान पर है। शीर्ष दस बड़े आबादी वाले देशों में से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापार संबंध रसातल में पहुंचे हुए हैं। इनके अतिरिक्त ब्राजील, नाइजीरिया, रूस व यूथोपिया के अधिक जनसंख्या वाले देशों तक भी भारतीय एफएमसीजी उत्पादों एवं सेवाओं का प्रसार करना होगा। इन देशों की बड़ी क्रयशक्ति वाले ग्राहकों की रुचि के अनुसार स्वदेशी निर्माण, विनिर्माण व निर्यातकों का यथोचित पूल बनाना होगा। इन तात्कालिक उपायों के अतिरिक्त अनेक दीर्घकालिक उपाय भी हैं, जो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को हर संकट, समस्या एवं चुनौती से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक खेती एवं कृषि। इस क्षेत्र में नवोन्नत प्रगति करके इससे संबंधित खाद्य उत्पादों के सबसे बड़े विक्रेता, निर्यातक व लाभार्जक के रूप में भारत की स्थापना अवश्य हो सकती है, क्योंकि दुनिया में बढ़ते स्वास्थ्य संकट, कृत्रिम व रसायन मिश्रित खाद्यान्नों की प्रचुरता से विश्व के लोग दुःखी हैं। इसी प्रकार भारत के पास आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा की विलक्षण योग्यता है।

इन उपायों के बल पर दुनिया का हरेक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करना चाहता है। भविष्य में इस क्षेत्र को भी भारत के अर्थतंत्र का बड़ा आधार स्तंभ बनाया जा सकता है। इन दीर्घकालिक उपायों को अपनाकर भारत भविष्य में अमेरिका हो अथवा कोई अन्य देश, उसके किसी भी टैरिफ युद्ध का प्रतिरोध करने में पूर्णरूपेण सक्षम हो सकेगा

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

व्यक्तित्व
कमल कटकी

उत्कृष्ट भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ थे 'भूपेन दा'

मुझे लगता है कि समग्र विश्व में ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा- जिसके पास गायक, गीतकार, संगीतकार, कहानी लेखक, निबंधकार, नाटककार, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, संगीत निर्देशक, अभिनेता, पत्रकार, साहित्यकार, पत्रिका संपादक, पुस्तक पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, बुद्धिजीवी आदि सभी गुण एक साथ हों। ऐसा ही एक व्यक्ति हैं डॉ. भूपेन हाजरिका। 1984 से भूपेन दा के एक गिटार वादक के रूप में 5 नवंबर 2011 को महाप्रयाण के दिन तक, अपने पच्चीस वर्षों से अधिक समय की निकटता के दौरान हर एक क्षण में, मैंने बहु-प्रतिभाशाली, बहुआयामी कर्मयोगी, भूपेन दा को करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 8 सितंबर, 1926 को उस समय के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के अधीन तथा आज के अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में स्थित एक छोटे से शहर सदिया से अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करने वाले भूपेन दा अपनी जीवन परिक्रमा को कठोर संघर्ष, सुख-दुख, उतार-चढ़ाव के बीच आगे ले जाते हुए खुद को एक वैश्विक कलाकार के रूप में स्थापित करना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी गुणवत्तापूर्ण

गीत-संगीत की रचनाओं के माध्यम से आम लोगों का दिल जीतने में सक्षम हुए थे। भूपेन दा की चिरस्थायी वैश्विक लोकप्रियता केवल उनके गीतों के कारण ही है, ऐसी बात नहीं है। मेरी दृष्टि में, भूपेन दा एक बरगद के पेड़ की तरह विशाल हृदय के व्यक्तित्व के धनी थे और इस पेड़ की जड़ें खारखोआ (मूल) असमिया थे, पूरे पेड़ समग्र भारत था और पेड़ की शाखाएं, उप-शाखाएं, पत्ते आदि विश्व-उन्मुख थे। बिहु, ब्रह्मपुत्र और भूपेन- अंग्रेजी वर्णमाला के तीन अक्षरों से समृद्ध इन शब्दों ने आज भी असम का परिचय विश्व के सामने उजागर करती है। भूपेन दा के सहयोगी के रूप में काम करने के कारण, असम के अलावा दुनिया भर के कई जाने-माने कलाकारों और हस्तियों से मिलने का अवसर मुझे मिला। लेकिन भूपेनदा जैसे महान व्यक्तित्व की सुगंध मुझे उनमें नहीं मिली। हमारे जैसे आम लोगों के लिए भूपेन दादा को समझ पाना मुश्किल है। उनमें विभिन्न रूपों का एक अद्भुत संयोजन था। क्रोध उनके जीवन का हमसफर जैसा था, ठीक उसी तरह जैसा उनके साथ हमेशा अपनी प्यारी मुस्कान रहती, जैसे धान के खेत की पराली तुरंत जलते ही थम जाती है, गुस्सा भी उसी तरह तुरंत गायब हो जाता है। पैसे के प्रति उनमें तनिक भी मोह नहीं था। उन्होंने मुझे कभी यह नहीं पूछा कि "फलाँ कार्यक्रम में गाने के लिए तुम्हें कितना मानदेय मिला?" या "मैं गाकर कितना कमा पाया?" यहां तक कि कार्यक्रम से संबंधित आय-व्यय का हिसाब-किताब जानने की कोशिश भी उन्होंने कभी नहीं की। पैसों के प्रति उनकी उदासीनता इतनी थी कि एक बार गुवाहाटी में आयोजित लता मंगेशकर के संगीत-प्रदर्शन का भारी-भरकम मानदेय लेकर भूपेन दा ने वह पैसों का थैला मुम्बई की टैक्सी में ही भूलकर छोड़ दिया था। धन के जोड़-घटाव से भूपेन दा का कोई लेना-देना नहीं था, वे जानते थे तो केवल शब्द और सुर का जोड़-घटाव, जनता से संवाद का जोड़-घटाव। आम लोगों के बीच रहकर असाधारण जीवन जीकर उन्हें बहुत संतोष मिलता था। साधारण जन के बीच रहकर खुश रहने वाले इस असाधारण भूपेन हजारिका ने समय से आगे चलकर अपनी जीवन-यात्रा को गहन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया और असम सहित सम्पूर्ण भारत में स्वयं को एक चिरस्मरणीय संगीतकार के रूप में स्थापित कर गए। राजपथ के किनारे आराम कर रहे रिक्शा चालक से वे कभी एक चुटकी खैनी लेकर अचानक ही गाने लगते थे -"मानुहे मानुहर बाबे, जदीहे अकनो ना भाबे"। उस क्षण कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही भूपेन हाजरिका हैं जिन्होंने पचास के दशक में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब भूपेन दा को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, तब डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने कहा था - 'डॉ. हजारिका, मैं हमेशा आपके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ?' तेजपुर विश्वविद्यालय ने इन दोनों महापुरुषों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। भूपेन दा के महाप्रयाण के कुछ दिन पहले स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भूपेन दा को दीपावली की शुभकामनाएं भेजते हुए जीवन-संघर्ष में विजय पाने का उत्साह दिया और कहा था- 'सभी उत्कृष्ट भारतीयों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं।' मेरी नजर में भूपेन दा एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे।

(लेखक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें

संकलित
दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट को स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी छवि के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य व्यक्ति अपने गलत कार्य या कथन की वैसी संरक्षा करेंगे जैसे सद्गुण या शील दांव पर हो।

ऐसे काम न करें, जिनसे गलत संदेश जाता है

संकलित
प्रेरणा

गुरुजी अपने शिष्यों को नियमित रूप से उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वे उपदेश दे रहे थे, उस समय एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आम लोग तो सभी सुख-सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन साधु-संतों के लिए इतने कठोर नियम क्यों हैं? परमहंस जी ने शिष्य से कहा कि हमें ऐसे काम करना चाहिए, जिनसे समाज को अच्छा संदेश मिलता है। ये बात साधु-संतों को खासतौर पर ध्यान रखनी चाहिए। आम लोग तो समाज में रहकर अनुशासन के साथ सभी काम कर सकते हैं, लेकिन साधु-संत को हर हाल में गलत कामों से दूर ही रहना चाहिए। साधु-संतों को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सुख-सुविधा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, संत को क्रोध से भी बचना चाहिए। तभी वे समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं। शिष्य ने फिर पूछा कि साधु-संतों के लिए ही इतने कठिन नियम क्यों हैं? जबकि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। परमहंस जी ने शिष्य को समझाया कि त्याग का संदेश साधु-संत नहीं देंगे तो और कौन दे सकता है। साधु-संत अपने ज्ञान और कर्म से समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने की सीख देते हैं। साधु-संत हमें बताते हैं कि हमें किसी भी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए, त्याग की भावना रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। परमहंस जी ने साधु-संतों के माध्यम से संदेश दिया है कि अगर हम घर-परिवार और समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए।

सोरहिया मेला

वाराणसी में 16 दिनों तक चलने वाले सोरहिया मेले के दौरान लोग अनुष्ठान करते हुए।

आज की पाती

साइबर क्राइम के बढ़ते कदम रोकने होंगे

जिस गति से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, यह आम आदमी के लिए एक मुसीबत बन गई है और लुटेरों के लिए जैसे मनोरंजन और लॉटरी लगी है। हैरानी इस बात की है कि इस मर्ज की दवा किसी के पास नहीं। किसी को जब चाहे, अपराधी बंधक बना कर सब कुछ लूट लेते हैं और उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देश में बड़ी संख्या में लोग इस क्राइम के शिकार हो रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर समस्या है और इससे आंख नहीं फेरी जा सकती। जहां डिजिटलाइजेशन के अनेक लाभ हैं, इससे कई गुणा हानियां भी हैं। द्वंद्व यह है कि इसे अपनाएं या नहीं? इस पर सभी को गंभीरता एवं शीघ्रता से समाधान निकालना होगा। आज नहीं तो कल हर कोई इसका शिकार होगा। यह एक चुनौती भी है। सभी को सचेत रहना होगा।

- विकास लाहोटी, रायगढ़

X ट्रेंड

'प्रतिभा सेतु' प्लेटफार्म

यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं में जो होनहार प्रतिभावी आखिरी मेरिट लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाते, उनके लिए 'प्रतिभा सेतु' डिजिटल प्लेटफार्म बनाया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इसकी मदद से उन्हें नए अवसर मिलने लगे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

निर्यात में गिरावट की आशंका

अमेरिकी टैरिफ से निर्यात में गिरावट की आशंका के कारण राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट निर्यातक भी परेशान हैं। इसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं कारीगरों एवं श्रमिकों के रोजगार पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए जल्द ठोस कदम उठाने होंगे।

-अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

चीन पर निर्भरता

चीन से आने वाले सामानों पर जिस तरह भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के लगातार घटते जा रहे काम-कारोबार पर पड़ा है। इससे बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही है।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

संवैधानिक जिम्मेदारी

गुजरात में भी बड़े पैमाने पर वोटों में धांधली का पर्दाफाश हुआ है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया देने व उनकी जाँच करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएगा या फिर यूँ ही चुपचाप बैठा रहेगा?

-जयराम रमेश, सांसद, कांग्रेस

करंट अफेयर

मैक्रों के फैसले से इजराइल और अमेरिका हुए नाराज

फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निर्णय के बाद अन्य पश्चिमी देशों ने भी इसी प्रकार के कदम उठाए जिसे लेकर इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका में नाराजगी है। इस फैसले ने गाजा में जारी विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों के केंद्र में दो-राष्ट्र समाधान को एक बार फिर से ला खड़ा किया। पिछले सप्ताह इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति मैक्रों ने लिखा, "फलस्तीनी जनता को उनका अपना राष्ट्र दिलाने के हमारे संकल्प की जड़ें इस विश्वास से जुड़ी हैं कि स्थायी शांति इजराइल की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। मैक्रों ने कहा, फ्रांस के कूटनीतिक प्रयास गाजा में उस भयावह मानवीय आपदा पर हमारे आक्रोश से उत्पन्न हुए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सात अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हमले के साथ शुरू हुए युद्ध में अब तक 63,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा ने कहा है कि वे 23 सितंबर से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के अपने संकल्प को औपचारिक रूप देंगे।

ऑफ बीट

एआई को प्रशिक्षित करने का डेटा खत्म हो सकता है

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच रही है, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उद्योग में प्रशिक्षण डेटा खत्म हो सकता है - वह ईंधन जो शक्तिशाली एआई सिस्टम चलाता है। यह एआई मॉडल, विशेष रूप से बड़े भाषा मॉडल के विकास को धीमा कर सकता है, और एआई क्रांति के प्रक्षेपवक्र को भी बदल सकता है। लेकिन वेब पर डेटा की मात्रा को देखते हुए, डेटा की संभावित कमी एक मुद्दा क्यों है? और क्या जोखिम से निपटने का कोई तरीका है? एआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा क्यों महत्वपूर्ण है? शक्तिशाली, सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले एआई एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी को 570 गीगाबाइट टेक्स्ट डेटा या लगभग 300 अरब शब्दों पर प्रशिक्षित किया गया था। इसी तरह, स्थिर प्रसार एल्गोरिथ्म (जो डीएएलएल-ई, लेंसा और मिडजर्नी जैसे कई एआई छवि-जनरेटिंग ऐप्स के पीछे है) को 5.8 अरब छवि-पाठ जोड़े वाले एलआईएओएन-5बी डेटासेट पर प्रशिक्षित किया गया था। यदि किसी एल्गोरिदम को अपर्याप्त मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो यह गलत या निम्न गुणवत्ता वाले आउटपुट उत्पन्न करेगा।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

40 अरब डालर से अधिक का निवेश किया है पिछले 11 वर्षों में जापानी कंपनियों ने भारत में, जिसमें 13 अरब डालर का निवेश पिछले दो वर्षों में हुआ है।

शिशिर शुक्ला
शिक्षक, स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय, शाहजहांपुर

आजकल

नए आयाम छूते भारत-जापान संबंध

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी आठवीं जापान यात्रा रही। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भारत-जापान संबंधों का दस वर्षीय आर्थिक रोडमैप प्रस्तुत किया। भारत और जापान के बीच बढ़ते संबंध न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी एक सकारात्मक संकेत हैं। यह सहयोग सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा

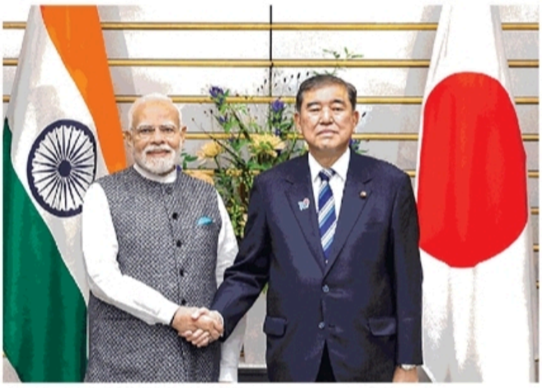

अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

आज वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य एक बड़ी उथल-पुथल की स्थिति से जूझ रहा है। चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध हो या अमेरिका की निरंतर बदलती टैरिफ नीतियां, सभी ने वैश्विक परिदृश्य को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। ऐसे में भारत और जापान का निकट आकर संबंधों की एक नई इबारत लिखना निश्चित रूप से वैश्विक पटल पर राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी की एक नई रेखा खींचेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय जापान यात्रा वास्तव में उनकी आठवीं जापान यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने भारत-जापान संबंधों का दस वर्षीय आर्थिक रोड मैप प्रस्तुत किया। दोनों देशों के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से जंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 13 समझौते हुए। जापान ने आने वाले दस वर्षों में भारत में 10 खरब येन अर्थात 5.99 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। यह समझौता आज के उथल-पुथल भरे आर्थिक एवं राजनीतिक वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के हितों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत और जापान के संबंध कोई नए नहीं हैं। जापान के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है और यह यात्रा आज भी अनवरत जारी है। वर्तमान की स्थितियों पर गौर करें तो तकनीक के मामले में जापान किसी सुपर पावर से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर, भारत तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक पटल पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। आज भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक विकास में भारत की भागीदारी 18 प्रतिशत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, पिछले 11 वर्षों में जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डालर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें 13 अरब डालर का निवेश पिछले दो वर्षों में हुआ है। भारत के संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि यहां पर श्रमशक्ति का एक बड़ा बाजार मौजूद है। यदि इस श्रमशक्ति को जापान जैसे उन्नत तकनीकी से लैस देश द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, तो निश्चित रूप से दोनों देश मिलकर उत्पादन एवं आर्थिकी के नए प्रतिमान गढ़ देंगे।

आज तेजी से बदलती भू-राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य बेतरतीब आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव प्रत्येक देश के हितों पर पड़ता नजर आ रहा है। यह स्थितियां भारत के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं हैं। जापान के साथ वैश्विक साझेदारी निश्चित रूप से भारत को इन चुनौतियों से निपटने में बड़ी मदद करेगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (चंद्रयान-5) के लिए भी समझौता हुआ है। इसके तहत चंद्रयान-5 मिशन जाक्सा के प्रक्षेपण यान एच3-24एल के द्वारा लांच किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में साझा भागीदारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगी। इसके अलावा, आतंकवाद एवं साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी दोनों पक्षों ने चिंता जताते हुए परस्पर सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच मानव संसाधन को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों में आने वाले पांच वर्षों में पांच लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। भारत के लगभग पचास हजार कुशल एवं अर्धकुशल पेशेवरों को जापान भेजा जाएगा, जो निश्चित रूप से दोनों देशों की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रतिभा के साथ उन्नत किस्म की तकनीकी का निवेश निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंधों एवं चतुर्मुखी प्रगति की एक मजबूत आधारशिला निर्मित करेगा। दोनों देशों के बीच बनी संयुक्त ऋण तंत्र सहमति आर्थिक समस्याओं से निपटने में वरदान साबित होगी। यह पूर्णतया निश्चित है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को गति तकनीक, प्रतिभा तथा श्रम शक्ति के संयोजन से ही मिलती है। भारत एवं जापान के नवीन द्विपक्षीय संबंधों से ये सभी जरूरतें बड़ी सहजता के साथ पूर्ण हो जाएंगी। आज का समय हरित ऊर्जा, नवाचार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। निश्चित रूप से भारत एवं जापान के मध्य हुए समझौते इन क्षेत्रों में प्रगति के नए अध्यायों का सृजन करेंगे। आर्थिक उथल-पुथल एवं चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब एक-दूसरे के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए विकास को गति प्रदान की जाए। आज पूरा विश्व अमेरिका की ऊटपटांग टैरिफ नीतियों से ग्रस्त है। यह अमेरिका की टैरिफ नीतियां ही हैं जिन्होंने पूरे वैश्विक परिदृश्य को अस्थिरता की ओर मोड़ दिया है।

भारत एवं जापान के संबंधों में जुड़ने वाले नवीन अध्याय निश्चित रूप से दोनों देशों को वैश्विक आर्थिक हलचल के दुष्प्रभावों से मुक्त होकर एक नई अर्थनीति को परिभाषित करने में मदद करेंगे। इस प्रकार, भारत और जापान के बीच बढ़ते संबंध न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी एक सकारात्मक संकेत हैं। भारत और जापान के संबंधों में जो नई दिशा और गहराई आई है, वह न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण विकास है। यह सहयोग न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। भारत और जापान के बीच बढ़ते संबंधों की यह यात्रा निश्चित रूप से एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो दोनों देशों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है।

नई विश्व व्यवस्था में संतुलन साधने की चुनौती

विशाल कुमार सिंह

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शक्ति-संतुलन और सामरिक हितों की जटिलता बढ़ती जा रही है। अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कभी मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो कभी कठोर शुल्क लगाकर आर्थिक दबाव बनाता है। भारत जैसे उभरते राष्ट्र के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक ओर अमेरिका से सामरिक सहयोग आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर उसके मनमाने फैसलों से उत्पन्न जटिलताओं का सामना करना भी अनिवार्य है। अमेरिका की शुल्क आधारित नीति ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। अमेरिका चाहता है कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अन्य देशों पर शुल्क और व्यापारिक शर्तें थोपे। भारत, जिसकी विदेश नीति 'स्वतंत्रता और बहु-ध्रुवीय संतुलन' पर आधारित है, हमेशा यह प्रयास करता रहा है कि किसी एक शक्ति पर निर्भर हुए बिना अपने हितों को साधे। जब अमेरिका ने शुल्क संबंधी नई नीतियां लागू कीं, तब भारत ने नए संवाद और कूटनीतिक उपायों की राह अपनाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया विदेश यात्राएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

जापान और चीन की यात्रा तथा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत संतुलित कूटनीति के जरिये अमेरिका और अन्य शक्तियों से संवाद साधना चाहता है। यह स्थिति केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक कूटनीति का हिस्सा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव ने भारत के सामने नए अवसर भी प्रस्तुत किए हैं। अमेरिका के संरक्षणवाद से परेशान चीन भारत को एक बड़ा बाजार और संभावित साझेदार मान सकता है। किंतु भारत को चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रति सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत के संबंधों को नए आयाम मिले हैं। जापान, जो तकनीकी और पूंजी निवेश में अग्रणी है, भारत के औद्योगिक विकास में सहयोग कर सकता है। वहीं, चीन, जो आर्थिक महाशक्ति है, भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है। भारत की कूटनीति का कौशल इसी में है कि वह जापान जैसे मित्र देशों से सहयोग प्राप्त करे और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देश के साथ संतुलन बनाए रखे।

भारत के लिए यह समय संवेदनशील है, क्योंकि वह न केवल एशिया की राजनीति में, बल्कि वैश्विक व्यापारिक व्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि भारत अमेरिका पर अधिक निर्भर हो जाए, तो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति कमजोर हो सकती है। इसलिए, भारत की रणनीति बहु-ध्रुवीय सहयोग पर केंद्रित है। वह अमेरिका, रूस, जापान, चीन और यूरोपीय देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है। ब्रिक्स, एससीओ, आसियान और क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि वह वैश्विक संतुलन की नीति पर चल रहा है। भारत को अमेरिका की शुल्क नीति और संरक्षणवाद से उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के लिए आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर समाधान खोजना होगा। भारत को अपने निर्यात में विविधता लानी होगी और आंतरिक बाजार को मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा संकेत देती है कि भारत वैश्विक स्तर पर नई साझेदारियां बनाने के लिए तैयार है।

भविष्य में भारत की कूटनीति का मार्ग संतुलन बनाए रखने पर आधारित होगा। अमेरिका की शुल्क नीति से उत्पन्न संकट का समाधान तभी संभव होगा जब भारत नए बाजारों की ओर कदम बढ़ाएगा और बहु-ध्रुवीय सहयोग की रणनीति पर कायम रहेगा। भारत की विदेश नीति और कूटनीति का वर्तमान दौर 'संतुलन साधने' का है। यदि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में सही संतुलन स्थापित कर लेता है, तो वह न केवल एशिया का, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक निर्णायक ध्रुव बनकर उभरेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

कुत्ते और कुत्तों की तरह लड़ते लोग

प्रवीण दत्त शर्मा

देश में मुद्दों की कमी नहीं है-महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बाढ़, लेकिन इन सबको किनारे रख दीजिए, असली राष्ट्रीय बहस आजकल एक ही है-कुत्ते। पार्क से लेकर संसद तक, फेसबुक से लेकर नगर निगम तक-हर जगह वही राग: ''कुत्ते रहने चाहिए'' बनाम ''कुत्ते हटने चाहिए''। हमारे मोहल्ले की मीटिंग में भी हालात ठीक वैसे ही थे जैसे देश की संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष की बहस। एक सज्जन खड़े होकर बोले-''हम कालोनी से हमारे प्यारे कालू को नहीं हटने देंगे, वह मोहल्ले का पहरेदार है, हमारी बहू-बेटियों की सुरक्षा उसी पर है।'' पीछे से एक आवाज आई-''भाई साहब, जिस दिन कालू ने आपकी बहू को प्यार से बाइट दे दी न, तब देखेंगे आपकी सुरक्षा।'' ''ठहर जा कुत्ते के बहाने बहू पर कटाक्ष करता है, कुत्ते कहीं के।'' ''तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता'' दूसरी ओर से भी त्यौरियां चढ़ गईं। चेयरमैन ने बीच बचाव करते हुए कहा-''क्या यार, हमें कुत्तों पर विमर्श करना है, कुत्तों की माफिक लड़ना नहीं है।''

कुत्ता विरोधियों के साथ ही कुत्ता प्रेमी भी इन दिनों मैदान में हैं। इनके लिए कुत्ता सिर्फ पैट नहीं, पैशन है-और इस पैशन के चक्कर में मोहल्ला, सड़क, पार्क-सब में कुत्तों का साम्राज्य कायम है। हर मोहल्ले में एक टामी होता है-उसका कोई मालिक नहीं होता, पर भक्त बहुत होते हैं। राजनीति के केंद्र में भी कुत्ते आ गए हैं। नेताओं को मालूम हो गया है कि जनता अब सड़क गड्ढों और सीवर की बदबू से ज्यादा कुत्तों पर गुस्सा करती है। जन भावनाओं को भुनाते हुए एक नेता जी ने वादा किया-''हम जीतते ही मोहल्ले से आवारा कुत्तों को हटा देंगे।''

इधर टीवी, इंटरनेट मीडिया 'कुत्तामय' होने से घबराए कुत्तों ने भी अपनी एक मीटिंग बुला ही ली। मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ-''इंसानों की उनकी लड़ाई जारी रखने दी जाए, क्योंकि इंसानों की ये आदत हमें रोजाना, हड्डी और हेडलाइन दिलाती है।'' सारे कुत्ते खुशी में भौंकते हुए अपने-अपने ठिकानों पर लौट गए। दूर किसी गली में इंसान फिर 'कुत्तों' को लेकर 'कुत्तों' की तरह लड़ रहे थे।

पोस्ट

मानसून के दौरान पर्वतीय राज्यों में हुई क्षति का गंभीर अध्ययन और पूर्व में विशेषज्ञों द्वारा दी गई चेतावनियों को समझने की जरूरत है। ऐसा लगता है मानो पूरा हिमालय ही धंसता जा रहा है।
हृदयेश जोशी@hridayeshjoshi

अंग्रेजी राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन एक समय के बाद उस साम्राज्य का भी पतन हुआ। असल में साम्राज्य बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सभ्यताएं हमेशा कायम रहती हैं।
सुनंदा वशिष्ठ@sunandavashisht

भारत-चीन संबंधों में सुधार के रुझान मुझे 2018 में वुहान और 2019 में मामल्लपुरम की याद दिलाते हैं, लेकिन फिर 2020 में गलवन घाटी की घटना घटित हो गई।
तन्वी मदान@tanvi_madan

गलवन घाटी में संघर्ष के बाद मोदी ने चीन के खिलाफ एकदम कड़ा रुख अपनाया था और अब टैरिफ के बाद अमेरिका के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। उन्होंने दुनिया में भारत का कद ऊंचा ही किया है।
प्रकाश सिंह@singh_prakash

भारतीय वसंत कुमार
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

दबाव की राजनीति की शुरुआत

संजय निषाद, निषाद पार्टी के मुखिया। फाइल

प्रदेश की राजनीतिक भूमि में क्षेत्रीय दलों के चुनावी दबाव का बीज अंखुआ रहा है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने का जोर भी दम भर रहा है। इस चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में अपनी दखल के लिए भाजपा की आगुआई वाले राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के सहयोगी क्षेत्रीय दल अपने जातीय आधार वाले वोटरों के लिए एजेंडा की तलाश में जुटे हैं। सरकार के साथ बिताए गए मंत्री पद के कार्यकाल में अपनों के लिए क्या किया, यह हिसाब लेने-देने का वक्त धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है। पहले मछुआ समाज की मांग पूरी नहीं होने और अनुसूचित जाति आरक्षण के मुद्दे पर विधान भवन घेरने की बात कह चुके योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने हाल में ही यह बयान देकर राजनीतिक तपिश तेज की है कि-'यदि उसे लगता है कि छोटे दलों से फायदा नहीं है तो वह (भाजपा) गठबंधन तोड़ दे।'

इसी माह दिल्ली में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह (16 अगस्त को) में अपना दल (एस) और सुभासपा नेताओं को जुटाने के बाद निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का छोटे दलों के सापेक्ष अगुआपन ज्यादा मुखर दिख रहा है। बाकी छोटे दल भी गठबंधन में अपने महत्व का पारा बढ़ाने की कवायद में हैं। अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे जाति-आधारित छोटे दल विशिष्ट जाति समुदायों (कुर्मी, निषाद, राजभर) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी राज्य के जाति-आधारित चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वांचल की राजनीति में इन तीनों दलों की मजबूत दखल भी है। निषाद पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि भाजपा निषादों की मांगों को दरकिनार करती रही तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। निषाद पार्टी का यह भी दावा है कि वह प्रदेश में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में है।

प्रदेश में करीब पांच दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर निषाद समाज का प्रभाव है। बीते विधानसभा चुनाव में छह सीट भी हासिल हुई थीं। निषादों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के वादे को लेकर संजय खुद को घिरा महसूस करते हैं। यह अभी अधूरा है। सामने पंचायत चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव है। इस स्थिति से नुकसान का उन्हें डर है। इधर, संजय निषाद को यह भी लग रहा है कि भाजपा पूर्व राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद को महत्व दे रही जयप्रकाश निषाद का बयान भी उन्हें असहज करता रहा है। ऐसे में अपनी नाराजगी दिखाकर संजय निषाद भाजपा पर दबाव बनाने का दांव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। भाजपा में एक स्वर यह भी है कि लोकसभा चुनाव में संतकबीरनगर सीट से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद की हार और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पप्पू निषाद की जीत का आकलन होना चाहिए। निषादों का वोट भाजपा में ट्रांसफर कराने में संजय निषाद कितने प्रभावी हैं, यह सवाल उठ रहा है। संजय निषाद के लिए सपा का साथ पाना भी बहुत आसान नहीं होगा। सपा इस बात को याद करेगी कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले संजय निषाद ने दिन में अखिलेश यादव के साथ प्रेस वार्ता की थी और उसी दिन शाम होते ही भाजपा गठबंधन का हिस्सा बन गए थे।

संजय निषाद ने दिल्ली के कार्यक्रम में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल को भी शामिल किया था। भाजपा और रालोद का विवाद भी विधानसभा के मानसून सत्र के समय सामने आया था, जब योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जयन्त चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि जो भी पार्टी जाट-बहुल रालोद के साथ गठबंधन करती है, उसका विनाश होता है और उसे चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। बाद में उन्होंने अपनी बात वापस ले ली थी। सूत्रों के अनुसार, मथुरा की छाता सीट से विधायक लक्ष्मी नारायण चौधरी का स्थानीय रालोद पदाधिकारी और पूर्व विधायक तेजपाल सिंह से गहरा मतभेद है। बयान की पृष्ठभूमि में यह अदावत भी रही हो।

इससे पूर्व जुलाई में, अपना दल (एस) ने अपनी पार्टी के बागियों को सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई थी। अपना दल (एस) के उपाध्यक्ष और मंत्री आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी सरकार से खफा चल ही रहे हैं। इधर, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुभासपा भी राजभर समुदाय के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा चाहती है। वह भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी मांग पर अडिग है। राजभर को मंत्रिमंडल में बहुत देर से दोबारा जगह मिली है।

भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार चुनाव में खुद को केंद्रित किए है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की एक विशेषता यह भी है कि स्वभावगत रूप से वह बहुत शांतचित्त हैं। प्रदेश अध्यक्ष यह बार-बार दोहरा रहे हैं कि-'गठबंधन के दलों में सबका सोच एक जैसा नहीं होता। कई बार एक पार्टी नेता दूसरे के बयान से नाराज हो जाते हैं, भले ही वे सहयोगी हों। यह बात उनके गठबंधन पर भी लागू है, पर जनकल्याण, गठबंधन की मजबूती और विकास के मुद्दे पर हम सब एकजुट हो जाते हैं।' दबाव की राजनीति की शुरुआत का अंत क्या गुल खिलाता है यह थोड़े दिन और समय के गर्भ में पड़ा रहेगा।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या बदले हालात में एक साझेदार के रूप में चीन पर भरोसा किया जा सकता है?

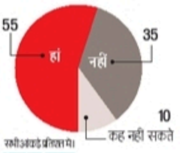

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या जीएसटी स्लैब में परिवर्तन को लेकर गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों का रवैया सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अर्थव्यवस्था 'डेड' हुई कहकर करे मजाक,
हाथी मर भी जाय तो कीमत होती लाख।
कीमत होती लाख इसे क्या जानें बुद्धू,
बस फैलाकर झूठ बेचते रहिए कद्दू!
जो फैलाते झूठ उन्हीं का कथता वस्ता,
बाकी तो मजबूत दिख रही अर्थव्यवस्था!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

रोहित कौशिक
वरिष्ठ पत्रकार

बचा लें बारिश के पानी को

इस समय देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। वर्षा के इस जल को हम जितना सहेज लेंगे और जमीन के अंदर जाने देंगे, उतना ही जल संकट को दूर रखेंगे

बारिश के पानी को बचाने के लिए करने होंगे ठोस प्रयास। फाइल

इस समय देश के कई हिस्से में अच्छी बारिश हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मानसून के दौरान बारिश के पानी को बचाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इस कारण बारिश में बड़ी मात्रा में जल बेकार बह जाता है। जल संरक्षण के माध्यम से हम बारिश के पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। इससे एक ओर जल संकट कम होगा, तो दूसरी ओर हम जल को बेकार बहाने के पाप से भी बच जाएंगे। कृषि की बढ़ती जरूरतों, खाद्यान्न उत्पादन, ऊर्जा उपभोग, प्रदूषण और जल प्रबंधन की कमजोरियों के कारण स्वच्छ जल पर दबाव बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि भारत में बारिश के मात्र पंद्रह प्रतिशत जल का ही उपयोग होता है, शेष जल बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है। इस मामले में इजरायल जैसे देश ने, जहां वर्षा का औसत 25 सेमी से भी कम है, एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। वहां जल की एक बूंद भी बेकार नहीं जाती है। अतिविकसित जल प्रबंधन तकनीक के कारण वहां जल की कमी नहीं होती है। जल संकट से निपटने के लिए हमें भी अपने देश में ऐसा ही उदाहरण पेश करना होगा। वर्षा के जल को जितना हम जमीन के अंदर जाने देंगे, उतना ही हम जल संकट को दूर रखेंगे। इस विधि से मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और हमारे देश को सूखे और अकाल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। एक आंकड़े के अनुसार, यदि हम देश के जमीनी क्षेत्रफल में से सिर्फ पांच फीसद क्षेत्र में होने वाली वर्षा के जल का संग्रहण कर सकें, तो एक अरब लोगों को प्रतिव्यक्ति सौ लीटर पानी प्रतिदिन मिल सकता है। आज हालात यह हैं कि वर्षा का 85 फीसद जल बरसाती नदियों के माध्यम से समुद्र में बेकार बह जाता है। फलस्वरूप निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। यदि इस जल को जमीन के भीतर पहुंचा दिया जाए, तो इससे एक ओर बाढ़ की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर भी बढ़ेगा।

जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि से हमारे देश में जल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सतही एवं भूमिगत दोनों ही स्रोतों से जल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भूमिगत जल पर हमारी निर्भरता कुछ अधिक ही है। भूमिगत जल की अत्यधिक निकासी से इसका जल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। गौरतलब है कि दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग सत्तर फीसद भाग जल से भरा हुआ है, लेकिन पीने लायक मीठा जल सिर्फ तीन फीसद ही है। शेष खारा जल है। इसमें से भी हम सिर्फ एक फीसद मीठे जल का ही उपयोग करते हैं। धरती पर उपलब्ध संपूर्ण जल, जल चक्र में चक्कर लगाता रहता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उद्योगीकरण एवं जनसंख्या विस्फोट के कारण जहां एक ओर जल प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जल चक्र भी बिगड़ता जा रहा है। हालांकि विश्व में उपलब्ध कुल जल की मात्रा आज भी उतनी ही है जितनी कि दो हजार साल पहले थी। अंतर है तो बस इतना कि उस समय पृथ्वी की जनसंख्या आज की तुलना में करीब तीन फीसद ही थी। हमारे देश में समस्त उपलब्ध जल के 90 प्रतिशत का उपयोग कृषि उत्पादन में किया जाता है, जिसमें खाद्य उत्पादन का अनुपात 35 प्रतिशत है। यदि कृषि उत्पादन में समुचित जल निकासी एवं जल उपयोग के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो बीस फीसद तक जल की बचत हो सकती है। इसी प्रकार दुनिया का लगभग 22 फीसद जल उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यदि औद्योगिक क्षेत्र पानी की बचत करना शुरू करे और पानी का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करे, तो इस संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है।

जल संकट से निपटने हेतु आज भी हमें अपनी पुरानी तकनीक को ही अपनाना होगा। हम स्वयं भी अपने मकान की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके मकान के नीचे भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर टैंक में जमा कर सकते हैं। प्रत्येक बारिश के मौसम में सौ वर्ग मीटर आकार की छत पर 65000 लीटर वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है, जिससे चार सदस्यों वाले एक परिवार की पेयजल और घरेलू जल आवश्यकताएं 160 दिनों तक पूरी हो सकती हैं। भारत जैसे देश में जहां पानी का प्रमुख स्रोत बरसात ही है, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या पानी को जमा करना बेहतर उपाय है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में जल संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वर्षा जल से सिंचाई की तकनीक विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। अथर्ववेद में जल को दवा कहा गया है, जबकि श्रीस्कंदपुराण में जलाशय निर्माण करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलने की बात कही गई है। हमें अभी से युद्धस्तर पर जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास शुरू कर देने चाहिए।

****

दैनिक जागरण

क्रियान्वयन के अभाव में अच्छी से अच्छी योजना भी व्यर्थ है

मोदी–चिनफिंग मुलाकात

यह स्वाभाविक ही था कि तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचती। इसका एक बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अपनी मनमानी और बेतुकी टैरिफ नीति से दुनिया को तंग करना और भारत को खासतौर से निशाने पर लेना है। यह एक अच्छा संकेत है कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने संबंधों को सुधारने और आपसी सहयोग बढ़ाने की बातें कीं। इन वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच नए सिरे से समझबूझ कायम हुई है, लेकिन बात तब बनेगी जब चीनी राष्ट्रपति अपने कहे के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करेंगे। इस पर निगाह रखना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि चीन अपने कहे से मुकरने और यहां तक कि उसके विपरीत कार्य करने के लिए जाना जाता है। दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की मुलाकात से ऐसा कोई अर्थ निकालना सही नहीं होगा कि भारत का चीन के प्रति भरोसा कायम हो गया है। एक तो आज के युग में किसी भी देश पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता और दूसरे भारतीय नेतृत्व न तो डोकलाम और गलवन घाटी की घटनाओं को भूल सकता है और न ही इसे कि चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात तो करता है, लेकिन भारत के मामले में प्रायः उलट रवैया अपनाता है। भले ही शंघाई सहयोग संगठन के एजेंडे में आतंकवाद से लड़ना भी शामिल हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चीन ने इस मुद्दे पर किस तरह भारतीय हितों के खिलाफ काम किया है। पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के समय चीन की भूमिका को ओझल नहीं किया जा सकता।

चीन से जो समझबूझ बनती हुई दिख रही है, उसे भारत को अपने हित में उपयोग करने के लिए हरसंभव प्रयत्न करने चाहिए। इन प्रयत्नों का यह अर्थ नहीं हो सकता कि भारत चीनी आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ा दे और उसके साथ जो व्यापार घाटा है, उसे कम करने के प्रयास न करे। ऐसे प्रयास तो भारत को करने ही होंगे। हां, फिलहाल उसकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि चीन के पास जो भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल वह अपने आर्थिक विकास में किस तरह करे? भारत का एकमात्र लक्ष्य एक ओर जहां शंघाई सहयोग संगठन के अनुकूल रवैये वाले देशों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अपने हितों की पूर्ति के लिए चतुराई से चीन का सहयोग लेना भी। इसका यह मतलब भी नहीं कि उसे अमेरिका से कोई दूरी बढ़ानी है। भारत की प्राथमिकता तो सभी समर्थ देशों से समर्थन लेकर अपना तेज आर्थिक विकास करने की होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें वास्तव में एक महाशक्ति बनना है तो आठ प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल करनी होगी।

हिमाचल की उपलब्धि

वर्तमान में बाजार को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए उपभोक्ता अधिकारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। भ्रामक विज्ञापनों, असुरक्षित उत्पादों या छिपे शुल्कों जैसी अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने के लिए यदि उपभोक्ता जागरूक नहीं होंगे तो यह उनके हितों को ही क्षति पहुंचेगी। सुखद है कि हिमाचल प्रदेश के लोग उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि उपभोक्ता मामलों के निपटारे में यह देश के चार शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इसके लिए जितनी प्रशंसा राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग की होनी चाहिए, उतनी ही उन उपभोक्ताओं की भी, जो अपने साथ गलत होने पर चुप नहीं रहे और उचित मंच पर आवाज उठाकर उपभोक्ता की जीत के नायक बने। यह उपलब्धि न केवल आयोगों की तत्परता दर्शाती है, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भावना को भी मजबूत करती है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रदेश का प्रदर्शन सकारात्मक संदेश देता है। राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला आयोगों ने अधिकांश मामलों का निपटारा करके यह सिद्ध किया है कि यदि इच्छाशक्ति और जवाबदेही हो तो लंबित मामलों का बोझ कम करना संभव है। हालांकि अब भी काफी कुछ करना शेष है। लंबित मामलों को पूरी तरह खत्म करना, ग्रामीण और दूरदराज के उपभोक्ताओं तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित बनाना और उपभोक्ता शिक्षा को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है।

> हिमाचल का उपभोक्ता मामले निपटाने में देश के चार शीर्ष राज्यों में जगह बनाना प्रशंसनीय है

ट्रंप रूपी आपदा को अवसर में बदलें

शिवकांत शर्मा

टैरिफ से निपटने के लिए जो उपाय करने होंगे, क्या उनके लिए हम आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, श्रम सुधार और कार्यसंस्कृति में सुधार करने के लिए तैयार हैं?

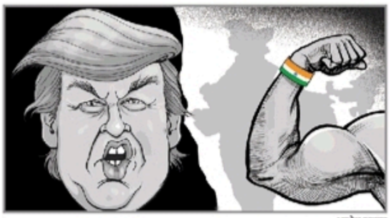

अवधेश राजपूत

पंचतंत्र की कथा है। एक तालाब में तीन मछलियां रहती थीं- अनागतविधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य। अनागतविधाता आने से पहले उपाय कर लेती थी। प्रत्युत्पन्नमति समस्या आने पर कुछ करती और यद्भविष्य भाग्य के भरोसे रहती थी। चीन को आप अनागतविधाता मान सकते हैं और भारत को प्रत्युत्पन्नमति, जो संकट सिर पर आने पर ही अपने हाथ-पांव मारता है। हम आजाद तो गांधी जी के स्वावलंबन के नारे के साथ हुए थे, मगर अन्न की आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति पर काम तब तक शुरू नहीं किया गया जब तक भयंकर अन्न संकट से दो-चार नहीं हुए। आर्थिक सुधार तब तक नहीं किए, जब तक 1991 में देश संरक्षणवाद और लाइसेंस राज की वजह से दिवालिया होने के कगार पर नहीं जा पहुंचा। उद्योगों में आत्मनिर्भरता की बात हमें तब तक याद नहीं आई जब तक कोविड महामारी ने आर्थिकी को ठप नहीं कर दिया। अब ट्रंप की अप्रत्याशित नीति ने विदेश व्यापार और विदेश नीति के मोर्चे पर हमारे लिए संकट खड़ा कर दिया, जिसके समाधान के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात दोहराई जा रही है।

टैरिफों को अपनी ही केंद्रीय अदालत द्वारा अवैध ठहराने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 वर्षों के सामरिक और आर्थिक संबंधों को ताक पर रखते हुए भारत पर लगाए टैरिफ को 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यही नहीं, भारत के सेवा क्षेत्र को निशाना बनाने वाले मोर्चे भी खोले जा रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस हर साल प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए 65 हजार और उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार वीजा देती है जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतीय पेशेवर और छात्र हासिल करते हैं। चूंकि सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियां एच-1बी वीजा के जरिये ही अपने प्रशिक्षित कर्मचारी अमेरिका भेजती हैं, इसलिए ट्रंप सरकार इसी पर अंकुश लगाना चाहती है। हालांकि खुद ट्रंप के कारोबार में एच-1बी वीजा पर आए पेशेवर काम करते हैं, पर उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और फ्लोरिडा के गवर्नर रान डेसेंटिस को एच-1बी वीजा की व्यवस्था घोटाला नजर आती है। गवर्नर डेसेंटिस ने तो यहां तक कहा है कि भारत ने इसे अमेरिकी व्यवस्था का दोहन करने का कुटीर उद्योग बना रखा है। ट्रंप सरकार अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एफ वीजा और एक्सचेंज छात्रों के जे वीजाओं पर भी कड़ी समय सीमाएं लगाने जा रही है। ग्रीन कार्ड की जगह भी 50 लाख डालर से मिलने वाले गोल्ड कार्ड शुरू किए जा रहे हैं जिनके सहारे ट्रंप अमेरिका के कर्ज को उतारना चाहते हैं। व्यापार और आप्रवासन को लेकर ट्रंप सरकार का यह रवैया भले नाटकीय लगे, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। उनके पहले कार्यकाल के कामों से और चुनाव प्रचार से इसके स्पष्ट संकेत मिल चुके थे। भारत की ऊंची आयात-शुल्क दरों और एच-1बी वीजा के मामले पर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी तनातनी हुई थी। भावी और अत्याधुनिक तकनीक को लेकर उनका संरक्षणवादी रवैया भी नया नहीं है, मगर भारत ने समय रहते इनसे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। क्रयशक्ति, उपभोग और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मंडी है। उसमें मिले प्रवेश का भारतीय व्यापारियों ने सामर्थ्य के हिसाब से पूरा लाभ उठाया, लेकिन क्या हम ऐसी वैकल्पिक मंडी तैयार कर पाए जहां भारतीय व्यापारी अमेरिका में राजनीतिक या आर्थिक अड़चनें खड़ी होने पर अपना माल बेच सकें। यूरोपीय संघ की मंडी अमेरिका का एक अच्छा विकल्प बन सकती थी। चीन ने मौजूदा हालात का पूर्वानुमान करते हुए यूरोप के साथ अपना व्यापार अमेरिका से भी अधिक बढ़ा लिया, परंतु भारत पिछले तीन साल से यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर अटका हुआ है। चीन ने अपना व्यापार आसियान की मंडियों में भी फैलाया। इसीलिए जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी तो चीन ने वाक् युद्ध में न उलझते हुए पहले बराबर का टैरिफ लगाकर और फिर उच्च प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों और चुंबकों के निर्यात को रोक ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया।

भारत भी अब यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यापार बढ़ाने और रक्षा, ऊर्जा, चिकित्सा, सेमीकंडक्टर और एआइ में आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मई 2020 में इसी के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, पर क्या उससे कुछ प्रगति हुई? प्रत्युत्पन्नमति मछली की तरह संकट मंडराने पर जरूर हम कुछ सुधार करते हैं। कुछ के नाम लेते हैं, पर संकट टलने के बाद भूल जाते हैं। जरूरत उन्हें जारी रखने की है। प्रधानमंत्री ने जापान में उद्योगपतियों से कहा 'कम, मेक इन इंडिया,' लेकिन क्या उसके लिए हम जरूरी आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, श्रम सुधार और कार्यसंस्कृति के सुधार करने के लिए तैयार हैं? जापान में हड़तालें न के बराबर होती हैं और तोड़फोड़ नहीं होती। क्या भारत में ऐसी कार्यसंस्कृति संभव है? सुधारों की जरूरत कृषि और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी है। चीन ने अपने इंजन बनाकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार कर लिए हैं। जबकि हमें विदेशी इंजन लगाकर भी तेजस को बनाते-बनाते 40 बरस बीत गए हैं। चीन अपना सामान बनाने में स्वचालन, एआइ या यंत्रबुद्धि और प्रशासन की निगरानी में इष्टतम प्रक्रिया का प्रयोग करता है। दुनिया की मंडियों में उसके माल से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को उससे भी कुशल उत्पादन प्रक्रिया अपनानी होगी।

आर्थिक सुधारों को 35 साल हो रहे हैं, पर क्या हम एक भी ऐसा ब्रांड बना पाए हैं जो अमेरिका, जापान के ब्रांडों की तरह वैश्विक हो? सालों से गूगल, माइक्रोसाफ्ट, फेसबुक और एपल की कोडिंग करते, बनाते और उन्हें चलाते आ रहे हैं, लेकिन चीन की तरह अपने बाइडू, वीचैट, टिकटाक और हुआवे क्यों नहीं बना पाए? चीन ने चैट जीपीटी के जवाब में आधा दर्जन एआइ माडल बना डाले, मगर भारत एक नहीं बना पाया। इसका कारण यह है कि भारत प्रायोगिक शिक्षा और अनुसंधान पर पूरा ध्यान नहीं देता। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होता तब तक भारत कोई शक्ति नहीं बन सकता।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

एनसीईआरटी की पहल पर आपत्ति क्यों

प्रणय कुमार

एनसीईआरटी ने उन परिस्थितियों को ही दर्शाया है, जिन्होंने विभाजनकारी मानसिकता को जन्म दिया

इतिहास की घटनाएं वर्तमान को दिशा देती हैं और वर्तमान उनसे सबक लेकर भविष्य की सुदृढ़ नींव रखता है। दुर्भाग्य से हमारे विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास और पाठ्यपुस्तकों में घटनाओं और तथ्यों को प्रायः यथार्थ से काटकर मिथ्या आदर्शों, भावुक नारों और दलगत पूर्वाग्रहों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। जब भी इतिहास को प्रामाणिक और वस्तुपरक ढंग से लिखने या पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसे अनावश्यक विवाद और शोर-शराबे का सामना करना पड़ा। सुधारों की इसी पृष्ठभूमि में एनसीईआरटी ने विभाजन की विभीषिका और उससे उपजी त्रासदी को निष्पक्ष दृष्टि से समझाने के उद्देश्य से कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दो विशेष पूरक शैक्षिक माड्यूल जारी किए हैं। इन्हें अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि चर्चा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों की सूक्ष्म और गहन समझ विकसित की जाएगी। इन माड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना, लार्ड माउंटबेटन और कांग्रेस को विभाजन का जिम्मेदार बताया गया है। कौन नहीं जानता कि जिन्ना की अंधी महत्वाकांक्षा, पद-लोलुपता और पृथक पहचान की राजनीति ने भारतीय मुसलमानों में पनप रही सांप्रदायिक भावना को भड़काने में निर्णायक भूमिका निभाई।

विभाजनकारी राजनीति के बीज पहले से ही सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इस्माइल जैसे नेताओं के विचारों में मौजूद थे। उनका सोच उस राजनीतिक इस्लाम से पोषित था, जो गैर-मुसलमानों के साथ स्थायी या समान संबंध की संभावना को सिद्धांततः नकारता था। इनका मानना था कि जिस इस्लाम की सदियों तक भारत में हुकूमत रही हो, उसे मानने वाले मुसलमान बहुसंख्यक आबादी वाले पंथनिरपेक्ष भारत में कैसे रह सकेंगे? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मुसलमान नेताओं के लिए पृथक देश की मांग के छिटपुट स्वर ही सुनाई पड़ते थे, किंतु मार्च 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद मुस्लिम लीग के नेतृत्व में विभाजन की मांग को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा घोषित 'डायरेक्ट एक्शन डे' ने विभाजन की दिशा लगभग तय कर दी। केवल कलकत्ता (कोलकाता) में ही कई हजार लोग मारे गए, जबकि नोआखाली (बंगाल) में 10 अक्टूबर 1946 को गुलाम सरवर हुसैनी के नेतृत्व में निर्दोष-निःशस्त्र हिंदुओं का पूर्व नियोजित नरसंहार हुआ। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार थी और हुसैन सुहरावर्दी मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे।

किन हालात में हुआ भारत का बंटवारा। फाइल

नोआखाली का नरसंहार किसी आकस्मिक उन्माद का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की धमकी- 'बंटा भारत या बर्बाद भारत' के समक्ष तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने घुटने से टेक दिए। जिन्ना मुसलमानों के बड़े तबके को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि मत-मजहब, संस्कृति, रीति-रिवाज, इतिहास और जीवन-दृष्टि जैसे सभी आधारों पर वे हिंदुओं से स्थायी रूप से भिन्न हैं। यही कारण था कि 1946 के संविधान-सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 78 में से 73 सीटों पर विजय प्राप्त की। मुस्लिम लीग को मद्रास, बांबे प्रेसीडेंसी और उड़ीसा में करीब सौ प्रतिशत, बंगाल में 95 प्रतिशत, मध्य भारत में 93 प्रतिशत, असम में 91 प्रतिशत, अविभाजित पंजाब में 86 प्रतिशत, बिहार में 85 प्रतिशत और संयुक्त प्रांत में 82 प्रतिशत सीटें प्राप्त हुईं। जिन तमाम मुसलमानों ने मजहब के आधार पर पृथक देश की मांग का समर्थन किया, उनमें से बड़ी संख्या में विभाजन के बाद भी भारत में ही रह गए, जबकि पाकिस्तान से भारत आए लगभग डेढ़ करोड़ हिंदू, सिख और सिंधी अपने ही देश में शरणार्थी बनकर दर-दर भटकते रहे। विभाजन से उपजी हिंसा में लगभग दस लाख से अधिक निर्दोष लोग मारे गए, लाखों परिवार अपने पुरखों की जमीन-जायदाद से उजाड़ दिए गए और माताओं-बहनों के विरुद्ध हुए अत्याचारों ने पाशविकता और अमानुषिकता की सारी सीमाएं पार कर दीं। मानव इतिहास का यह सबसे बड़ा विस्थापन किसी प्राकृतिक आपदा या बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ। इसके लिए अपने ही लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार थे।

1942 के क्रिप्स मिशन और 1946 के कैबिनेट मिशन में विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं था, फिर भी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना तुरंत क्यों स्वीकार की गई, यह प्रश्न आज भी भारतीय जनमानस को क्षुब्ध करता है। मार्च से अगस्त 1947 के बीच माउंटबेटन द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ हुई 133 बैठकों से स्पष्ट है कि विभाजन उनकी सहमति से हुआ। सत्ता-हस्तांतरण की तिथि जून 1948 से घटाकर अगस्त 1947 करना और सीमाओं के निर्धारण के लिए केवल पांच सप्ताह का समय देना घोर लापरवाही थी। सीमा-रेखांकन का दायित्व जिस सीरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया, वह न भारत की भौगोलिक वास्तविकताओं से परिचित था, न सांस्कृतिक जटिलताओं से। यदि एनसीईआरटी विभाजन की परिस्थितियों को रेखांकित करने की दिशा में पहल कर रहा है, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ध्यान रहे जो राष्ट्र अपने अतीत से सीख नहीं ग्रहण करता, वह उसे दोहराने को अभिशप्त होता है। इसलिए इतिहास का सही अध्ययन आवश्यक है।

(लेखक शिक्षाविद हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जागरूकता

अनुभव, अवसरों, परिस्थितियों एवं संघर्षों की अनवरत यात्रा ही जीवन है। इस सतत यात्रा में जागरूकता ऐसी शक्ति है, जो हमें बाह्य जगत की वास्तविकता से परिचित कराती है। जागरूकता की शक्ति ही हमें अपने अंतर्मन से भी जोड़ती है। जागरूकता का अर्थ है-किसी भी विषय के प्रति सजगता एवं सतर्कता का परिचय देते हुए हुए अधिकतम ज्ञानार्जन का प्रयास करना। वास्तव में जागरूकता एक विस्तृत एवं गहन अवधारणा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक स्तर पर हमें जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही सोच, विचार, तर्क-वितर्क एवं आत्ममंथन की शक्ति से संपन्न बनाया है। जागरूकता का संबंध केवल हमारी बाहरी इंद्रियों से ही नहीं है, अपितु हमारी भावनाओं, विचारों एवं कल्पनाशक्ति का भी जागरूकता के साथ एक नितांत गहरा संबंध है। जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब हम इसे जागरूकता के साथ जीने का प्रयास करें। जागरूकता को अपनी दिनचर्या में समावेशित करके हम जीवन की अनंत गहराइयों में उतरकर इसके वास्तविक मर्म को समझने में सफल हो सकते हैं।

सही अर्थों में जीवन और जागरूकता एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी विषय के प्रति जागरूकता उस विषय में हमारी समझ को विकसित बनाने में सहायता करती है। यदि हम स्वयं के प्रति जागरूक हों, तो हम निश्चित रूप से आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। यदि हम समाज एवं राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं, तो निश्चित ही हम उसकी प्रगति में अपना अमूल्य योगदान कर सकेंगे। यदि हम अध्यात्म के प्रति जागरूक हैं, तो यह जागरूकता ईश्वर से जुड़ने में हमारी मदद करेगी। जहां एक ओर जागरूकता का अभाव जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म देता है, वहीं जागरूकतामय जीवन सफलता के सोपान पर अग्रसर करता है।

प्रेरणा अवस्थी

स्मार्टफोन की गुलामी से मुक्ति की पहल

ढोंढ़राज सुथार

स्मार्टफोन की लत से 'फियर आफ मिसिंग आउट' की समस्या बढ़ रही है

जापान ने अपने लोगों को स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने का सुझाव दिया है। इसके तहत उसने दो घंटे प्रतिदिन और रात में निर्धारित समय के बाद इसके उपयोग को बंद करने का सुझाव दिया है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए रात नौ बजे और किशोरों एवं वयस्कों के लिए रात 10 बजे के बाद स्मार्टफोन का उपयोग न करने का आग्रह किया गया है। यह कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि एक नैतिक आग्रह है, किंतु इसका प्रतीकात्मक संदेश महत्वपूर्ण है। इस कदम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। स्मार्टफोन अब केवल एक फोन नहीं रहा, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, इसकी मौजूदगी हर क्षण हमारे जीवन को संचालित कर रही है। बच्चे खेल के मैदानों को छोड़कर वर्चुअल गेम्स में खो से गए हैं, युवा रियल टाइम रिश्तों की बजाय इंटरनेट मीडिया के जाल में उलझे रहते हैं। बड़े-बुजुर्ग भी इस डिजिटल नशे से अछूते नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप नींद का हराम होना, आंखों का कमजोर होना, मानसिक अवसाद का बढ़ना और सामाजिक अलगाव का जन्म होना आम बात हो गई है। परिवार एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बन गए हैं।

जापान की इस पहल के पीछे बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर उसकी चिंता है। हालांकि इस सुझाव के बाद वहां आलोचनाओं का तूफान भी उठ खड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि दो घंटे में तो एक पूरी फिल्म भी नहीं देखी जा सकती। पढ़ाई, रिसर्च, व्यावसायिक काम, परिवारजनों से संपर्क, सब कुछ के लिए स्मार्टफोन आवश्यक हो गया है। ऐसे में यह सीमा कैसे व्यावहारिक है? यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल भी उठता है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि सरकार हर निजी मामले में दखल दे। व्यक्ति को अपनी जीवनशैली चुनने का हक है, बशर्ते वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। राज्य की भूमिका जागरूकता फैलाने की हो सकती है, सीधे नियंत्रण की नहीं। फिर भी, हमें रुककर सोचना होगा कि क्या हम तकनीक के मालिक हैं या उसके गुलाम बन चुके हैं?

स्मार्टफोन की लत से 'फियर आफ मिसिंग आउट' की समस्या बढ़ रही है। यह तकनीक, जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बनी थी, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। समाधान केवल समय सीमा में नहीं है, बल्कि हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। तकनीक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ उपयोग की आदत का निर्माण ही स्थायी समाधान है। वैश्विक स्तर पर यह समस्या केवल जापान की नहीं है। भारत, यूरोप और अमेरिका में भी स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां तकनीक हमारी मालिक हो या हम तकनीक के मालिक बनकर उसका संयमित उपयोग करना चाहते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चीन के साथ सतर्कता भी जरूरी

'चीन से सहयोग की संभावनाएं' शीर्षक से प्रकाशित लेख में संजय गुप्त ने भारत के लिए संदेहास्पद रहे चीन के साथ सहयोग की जिन संभावनाओं को उकेरा है, वह विचारणीय हो सकती हैं। चीन भारत का पड़ोसी देश होने के साथ एशिया महाद्वीप में भारत की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान देश है। अपने व्यापारिक हितों के लिए वह भारत से संबंध तो रखना चाहता है, लेकिन भारतीय सीमा में सैन्य घुसपैठ कर जमीन कब्जाने की बुरी नीयत से भी बाज नहीं आता। इसी कारण वह भारत के लिए विश्वसनीय नहीं बन पाया। वर्तमान में अमेरिका की मनमानी टैरिफ नीति से भारत और चीन दोनों के व्यापारिक हित प्रभावित हुए हैं। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के बहाने होने वाली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा महत्वपूर्ण हो गई है। उधर नए घटनाक्रम में एक अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति को अवैध बताकर ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया है। टैरिफ नीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब अलग-थलग पड़ते दिख रहे हैं। भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी पर रोक लगाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। यह ट्रंप के लिए जबरदस्त झटका होगा। ऐसे में भारत को अपने हित साधते हुए बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ना होगा। अपनी कूटनीति से चालाक चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाने का यह अवसर भारत को अपने पक्ष में भुनाना होगा। इसमें चीन और भारत दोनों के मित्र रूस का सहयोग लेने भी भारत को नहीं चूकना चाहिए।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़ (उप्र)

मेलबाक्स

युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता की कीमत

युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना कभी आसान नहीं होता। कई साहसी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी जगहों से रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि युद्ध क्षेत्रों में पत्रकारों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होती है, लेकिन वास्तव में अधिकांश समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पत्रकारों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है और आम लोगों को जिन कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी खबरें भी उन्हें ही पहुंचानी पड़ती हैं। ऐसे पत्रकारों का काम सैनिकों से कम खतरनाक नहीं होता। बल्कि कभी-कभी सैनिकों से भी ज्यादा जोखिम उनकी जान को होता है। यह बात हमास और इजरायल के युद्ध में भी साबित हुई है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 200 पत्रकार अब तक मारे जा चुके हैं।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

प्रकृति की मार

जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के अधिसंख्य क्षेत्रों एवं इलाकों में भारी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बादल ऐसे फट रहे हैं, जैसे बमवर्षक विमान बम के गोले बरसा रहे हैं। भूस्खलन एवं पहाड़ ऐसे धस रहे हैं, जैसे कागज के महल। कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। प्रकृति एवं बादलों का यह रौद्र रूप हृदयविदारक एवं दहशत पैदा करने वाला है। बस्तियों की बस्तियां उजड़ रही हैं, क्या लोग, क्या मवेशी, क्या गाड़ियां, सब तिनके की तरह बह एवं मर रहे हैं। रावी, व्यास, भागीरथी, गंगा जितनी भी इन क्षेत्रों में नदियां हैं, ऐसे डरा रही हैं, जैसे साक्षात यमराज प्राण हरने हेतु लालियत हैं। मजबूत से भी मजबूत मकान, पूल पुलियाएं ताश के महल की तरह बह एवं गिर रहे हैं। जीने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, जो जिंदा बचे हैं, उनकी काया जान रही है। जानों के साथ माल का कितना नुकसान हुआ है एवं हो रहा है, आंकड़ों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। इस विनाशकारी समस्या के सकारात्मक समाधान खोजने होंगे। देश श्रम एवं धन की बेतहाशा बर्बादी सह नहीं सकता। प्रकृति के इस बादल फाड़ रौद्र रूप को समझने की दरकार है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सेना के जवान, इंजीनियर, एनडीआरएफ की टीमें, होमगार्ड जवान एवं अन्य जो भी सुरक्षा एवं बचाव में दिन-रात, खून-पसीना एक कर रहे हैं, वे साधुवाद एवं प्रणाम के पात्र हैं, जो स्वयं की जान की परवाह किए बिना जान-माल बचाने में लगे हैं।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

एकता का महत्व एक शाश्वत आश्चर्य है।
-रवींद्रनाथ टैगोर

एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीति में आ रहे एक बड़े बदलाव का इशारा करती है। अब जरूरी है कि दोनों देश इस अवसर का उपयोग करते हुए आपसी विश्वास को मजबूत कर सहयोग के नए रास्ते तलाशें।

हवा बदल रही है

तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीति में आ रहे एक बड़े बदलाव का प्रतीक बनी है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण यात्रा और अब प्रधानमंत्री मोदी का चीनी राष्ट्रपति से मिलना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होने के साथ वैश्विक मंच पर दोनों देशों की रणनीतिक स्वायत्तता और सहयोग की संभावनाओं को भी रेखांकित करता है। यह इस अर्थ में भी अहम है कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तकरार के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा है। अभी कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने चीन को आड़े हाथों लिया था, ऐसे में, दोनों शीर्ष नेताओं की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता की बात उठना और इस मुद्दे पर मोदी का जिनपिंग को साथ आने के लिए कहना यह दर्शाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के पक्ष में जरा भी बदलाव नहीं आया है। इस दौरान, वीजा, सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर यात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर सहमति भी दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने का ही इशारा करती है। दूसरी तरफ, ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस दुनिया की साठ फीसदी से भी बड़ी आबादी के घर यानी एशिया में रणनीतिक व कूटनीतिक स्तर पर दशकों से किए गए अपने प्रयासों से निर्मित अमेरिकी आधार को कमजोर कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका में अपीलीय न्यायालय द्वारा ज्यादातर टैरिफ को गैर-कानूनी करार देने के बाद अब ट्रंप के लिए घरेलू स्तर पर मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल, ट्रंप के टैरिफ से उपजी भू-राजनीतिक हवाएं ही भारत और चीन को नजदीक ले आई हैं, जिससे अमेरिकी नेतृत्व वाले क्वाड समूह के भविष्य पर प्रश्नचिह्न तो लगा ही है, इससे एक नया ताकतवर एशियाई व्यापार गुट भी तैयार हो रहा है। अमेरिका के बाद बीजिंग निस्संदेह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन का भारतीय उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने का आश्वासन भी भारत के लिए राहत की बात है, लेकिन अमेरिका की तुलना में चीन के साथ करीब दोगुना व्यापार घाटा एक ऐसा बिंदु है, जिस पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। साथ ही, चीनी रवैये के पुराने अनुभव के मद्देनजर भारत को सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने की भी जरूरत है। बहरहाल, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ने भारत और चीन के संबंधों को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया है। अब दोनों देशों को इसका उपयोग कर आपसी विश्वास को मजबूत करते हुए सहयोग के नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए।

एशियाई भू-राजनीति में नया अध्याय

चीन से पहले प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा ने भारत और जापान के बीच एक रणनीतिक तालमेल का सूत्रपात किया है। यह साझेदारी एशिया में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां भारत और जापान न केवल साझेदार के रूप में, बल्कि एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में एकसाथ चलेंगे।

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी और रणनीतिक गहराई से भरी बैठक ने ऐसे समय में भारत-जापान संबंधों में मजबूती के नए दौर की नींव रखी है, जब दोनों देश अनिश्चित वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। संदेश स्पष्ट था-भारत और जापान हिंद-प्रशांत व्यवस्था को आकार देने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। यह एक ऐसी साझेदारी का प्रतीक है, जो तात्कालिक लाभ से आगे विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और चीन की हठधर्मिता, ट्रंप की टैरिफ नीतियों और क्षेत्रीय अस्थिरता को संतुलित करने के साझा संकल्प पर आधारित है। इस शिखर सम्मेलन में प्राथमिकता वाले तीन क्षेत्रों की पहचान की गई, जो भारत-जापान सहयोग की दिशा निर्धारित करेंगे।

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

रक्षा और सुरक्षा: दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अब साइबर सुरक्षा और युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक विस्तारित होंगे। जापान की उन्नत समुद्री निगरानी क्षमताएं हिंद महासागर में भारत की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति का पूरक होंगी।

आर्थिक लचीलापन: अगले पांच वर्षों में 35 अरब डॉलर के जापानी निवेश के एक महत्वपूर्ण पैकेज की घोषणा की गई, जिसका लक्ष्य भारत की हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं, सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्रों और हरित हाइड्रोजन पहलों पर केंद्रित है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अनुरूप है और जापानी कंपनियों को एक विशाल और बढ़ते बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।

लोगों के बीच आदान-प्रदान: दोनों नेताओं ने छात्र और शोध छात्रवृत्तियों का विस्तार करने, जापान में भारतीय पेशेवरों के लिए कार्य वीजा को सुव्यवस्थित करने और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इससे सामाजिक जुड़ाव मजबूत होगा, जो आर्थिक और सुरक्षा ढांचे का पूरक होगा।

भारत को लाभ: इस यात्रा से भारत को कई लाभ हुए हैं। पहला, जापान के समर्थन को मजबूत करके भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) में अपनी स्थिति मजबूत की है। स्टील्थ पनडुब्बी तकनीक और ड्रोन प्रणालियों सहित रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाने की जापान की इच्छा, भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करती है। दूसरा, जापान सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और हरित प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बना हुआ है। जापान के साथ सहयोग सुनिश्चित करता है कि भारत भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पीछे न रहे। तीसरा, भारतीय निर्यात पर ट्रंप के भारी टैरिफ लगाए जाने के दौर में जापान भारत को एक वैकल्पिक स्थिर बाजार प्रदान करता है। दोनों पक्ष भारत के निर्यातकों को अमेरिकी व्यापार झटकों से बचाने के लिए तरजीही व्यापार सुविधा पर बातचीत करने पर सहमत हुए। चौथा, जापान ने दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति अनुबंधों और हाइड्रोजन ईंधन में संयुक्त उद्यमों के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिससे अस्थिर पश्चिम एशियाई आपूर्ति पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। पांचवां, मोदी की यात्रा ने एशिया के शक्ति संतुलन में भारत को एक अपरिहार्य भागीदार के रूप में स्थापित किया। ऐसे समय में जब चीन का दबदबा है, जापान के साथ खड़े होने का प्रभाव एक स्थिर शक्ति के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

अमेरिका पर असर: क्षेत्रीय व्यापार और आपूर्ति शृंखला एकीकरण के लिए भारत और जापान की नई प्रतिबद्धता अमेरिका के प्रभाव को कम करती है। ट्रंप के टैरिफ ने अनजाने में भारत और जापान को करीब ला दिया है, जिससे एक ऐसा क्षेत्रीय आर्थिक ढांचा तैयार हुआ है, जो अमेरिकी प्रभुत्व को दरकिनार कर देता है। भारत के साथ गहन रक्षा सहयोग की ओर इशिबा का झुकाव टोक्यो की सुरक्षा संबंधी नीतियों में विविधता लाने का संकेत है, जिसका मतलब है कि हिंद-प्रशांत गठबंधनों को आकार देने में अमेरिकी प्रभाव कम होगा। भारत-जापान सेमीकंडक्टर साझेदारी, अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के विकल्प के रूप में उभर सकती है। यह एशियाई तकनीकी आपूर्ति शृंखलाओं को अमेरिकी नियंत्रण में रखने के ट्रंप के प्रयासों को चुनौती दे सकती है। साथ ही यह अमेरिका के लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण की तुलना में भारत की बढ़ती कूटनीतिक चपलता को रेखांकित करती है। नतीजतन एशिया के उभरते शक्ति संतुलन में ट्रंप की केंद्रीयता कम होगी तथा सौदेबाजी की शक्ति भी घटेगी।

जापान को फायदा: भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में पाकर बीजिंग की जबर्दस्ती की रणनीति के समक्ष अब जापान के अलग-थलग पड़ने का खतरा कम हो गया है। पहले से ही चीनी आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता से चिंतित जापानी कॉरपोरेशन भारत को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखते हैं। भारत का 1.4 अरब लोगों का विशाल बाजार बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसर प्रदान करता है। घरेलू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे शिगेरु इशिबा, भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के जरिये अपनी विदेश नीति की सफलता को दर्शा सकते हैं। जापान की आबादी वृद्ध होती जा रही है। भारत के युवा कार्यबल की मेहनत और कौशल गतिशीलता जापान के मानव संसाधन अंतराल को भर देगी, जबकि भारतीय पेशेवरों को उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर मिलेंगे।

व्यापक एशिया पर प्रभाव: भारत-जापान शिखर सम्मेलन की गूंज पूरे एशिया में कई मायनों में सुनाई देगी। छोटे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश, जो अक्सर अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में फंसे रहते हैं, भारत-जापान धुरी को तीसरी स्थिर शक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे। यह उन्हें वाशिंगटन या बीजिंग के साथ विशेष रूप से जुड़े बिना कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ने की गुंजाइश देता है। यह साझेदारी दक्षिण एशिया और अफ्रीका में कनेक्टिविटी को नया रूप दे सकती है, तथा चीन के बीआरआई को चुनौती दे सकती है। भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच तालमेल चीन की आक्रामकता को रोक सकता है, जिससे एशिया के सामुद्रिक क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा ने भारत और जापान के बीच एक रणनीतिक तालमेल का सूत्रपात किया है। यह साझेदारी एशिया में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां भारत और जापान न केवल साझेदार के रूप में, बल्कि एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में एकसाथ चलेंगे।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

लू होल्ट्ज

खेल हमें मेहनत करने के अलावा एक और सबक सिखाते हैं, जीवन के हर पल को जीना और आनंद लेना। अक्सर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के सफर का आनंद नहीं ले पाते।

नजरिया ही जीवन को सुंदर बनाता है

जब आप तीन सरल नियमों का पालन करेंगे, तभी अच्छे विकल्प पा सकते हैं। जो सही है वह करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और लोगों को दिखाएं कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं। सही पथ पर चलना और काम करना ही विश्वास जीतने का एकमात्र तरीका है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और लोगों को यह दिखाकर कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप प्यार या एक-दूसरे के लिए भावना दिखा रहे हैं। इस तरह आप उत्कृष्टता के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होते हैं। यह संदेश इतना सरल है कि मुझे कभी चौथे नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी। चाहे आप किसी टीम में हों, या किसी कंपनी का हिस्सा हों या अपने परिवार के साथ घर पर हों, आप हमेशा कठिनाइयों और चिंताओं से जूझते रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो या आपने कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हासिल कर ली हों।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा आलोचना करने के बजाय, गलती करने वाले से यह कहना चाहिए कि तुम यह काम और बेहतर तरीके से कर सकते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसके काम को सुधारना चाहते हैं, न कि उसकी व्यक्तिगत निंदा कर रहे हैं।

यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति की आलोचना करने से वह हतोत्साहित होता है और नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन उसके काम की आलोचना करने से सुधार की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा, मुश्किल समय में लोगों को डांटने के बजाय समझाना और सहानुभूति दिखाना ज्यादा प्रभावी होता है। मैं अक्सर दो सबसे महत्वपूर्ण दिनों के बारे में सोचता हूं, जिस दिन इन्सान का जन्म होता है, और जिस दिन हमें पता चलता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। और वह कारण क्या है? दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। जब मैं नोट्रे डेम में कोच था, तो मैंने खिलाड़ियों से कहा कि अगर वे चार साल तक मेरी हर बात मानेंगे, तो मैं अगले चालीस साल तक उनकी हर बात मानूंगा। शुक्र है, वे चालीस साल अब पूरे हो चुके हैं। वे मुझे थका रहे थे। हर हफ्ते चार-पांच खिलाड़ी मुझसे संपर्क करते हैं। खेल हमें मेहनत करने के अलावा एक और सबक सिखाते हैं, जीवन के हर पल को जीना और आनंद लेना। अक्सर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के सफर का आनंद नहीं ले पाते। अपने बच्चों, अपने नाती-पोतों के साथ अपने जीवन का आनंद लें और जो कर रहे हैं, उसमें मजा करें। यह सब विकल्पों पर निर्भर करता है और हर दिन आप जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करते हैं, वह है आपका नजरिया, आप चीजों को कैसे देखते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं और हमारा नजरिया कैसा है।

मुश्किलों का सामना करें

हमारा औसत जीवनकाल करीब सत्तर साल है, इसलिए जब तक सांसें हैं, सही काम करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, और दूसरों की परवाह करें।

सूत्र

मुश्किलों का सामना सकारात्मक नजरिये से करें। काम की आलोचना करें, व्यक्ति की नहीं। दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ें और जीवन का आनंद लें। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ करें ।

दूसरा पहलू

लोग बुलिंग करना क्यों सीख जाते हैं? घर का माहौल, टीवी व वीडियो गेम्स उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं?

कैसे टीवी, वीडियो गेम्स बुलिंग को प्रेरित करते हैं

कई दशकों के शोध ने साबित किया है बुलिंग (परेशान करना) हमारे जीवन को खोखला कर देती है। इससे प्रताड़ित बच्चों और किशोरों में चिंता, अवसाद, स्कूल छोड़ने, साथियों द्वारा नकारे जाने, सामाजिक अलगाव और आत्म-क्षति का खतरा रहता है। वयस्कों को भी अक्सर नौकरी पर धमकाया जाता है, और वे भी बच्चों की तरह ही प्रताड़ित होते हैं। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं बच्चों और किशोरों के विकास पर अध्ययन करती हूं। इस अध्ययन में यह समझना भी शामिल है कि लोग परेशान क्यों करते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। कोई ताकतवर व्यक्ति, जैसे स्कूल का कोई दबंग बच्चा या ऑफिस का बॉस, किसी कमजोर व्यक्ति को बार-बार परेशान करता है, चिढ़ाता है या चोट पहुंचाता है, तो उसे बुलिंग कहते हैं। यह कई तरह से हो सकती है, शारीरिक जैसे- धक्का देना या चोट पहुंचाना। सामाजिक- दोस्तों के ग्रुप से बाहर करना। यौन उत्पीड़न- अनुचित टिप्पणियां करना। कभी-कभी किसी को उसकी जाति, धर्म, यौन रुचि या शारीरिक बनावट की वजह से निशाना बनाया जाता है। जैसे, मोटापे से ग्रस्त लोग या कोई शारीरिक अक्षमता वाले लोग ज्यादा निशाने पर रहते हैं। इससे उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

सारा गोल्डस्टीन

बुलिंग हमारे जीवन को खोखला कर देती है। इससे प्रताड़ित बच्चों व किशोरों में चिंता, सामाजिक अलगाव का खतरा रहता है।

यदि बच्चे ऐसे घर में बड़े होते हैं, जहां दया और आत्मीयता नहीं होती और घर में माता-पिता आपस में झगड़ते हैं, तो बच्चे आगे चलकर उसे अपनाते हैं और अपने साथियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं।

लोग बचपन में ही बुलिंग करना सीखते हैं। इसे 'मनोवैज्ञानिक मॉडलिंग और सामाजिक शिक्षा' कहते हैं। यानी, बच्चे दूसरों को बुलिंग करते देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। मीडिया का उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे- टीवी, फिल्में, वीडियो गेम्स और गाने में जब हिंसा या बुरा व्यवहार दिखाया जाता है, तो बच्चे उसकी नकल करते हैं। इसमें परिवार का भी बहुत योगदान होता है। यदि बच्चे ऐसे घर में बड़े होते हैं, जहां दया और आत्मीयता नहीं होती, बल्कि उन्हें खूब शारीरिक दंड मिलता है और घर में माता-पिता आपस में झगड़ते हैं, तो बच्चे आगे चलकर उसे अपनाते हैं और अपने साथियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यदि बच्चा बुलिंग करने वाले दोस्तों के साथ रहता है, तो संगति में वह भी ऐसा करने लगता है। कोई अपना काम निकालने के लिए डराता-धमकाता है, तो किसी को गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। अगर आप बुलिंग के शिकार हैं, तो किसी भरोसेमंद बड़े से बात करें, जैसे माता-पिता, शिक्षक, प्रिंसिपल या काउंसलर। वे आपकी मदद करेंगे। अगर ऑफिस में बुलिंग हो रही है, तो अपने मानव संसाधन विभाग से बात करें। कानून भी आपकी रक्षा करता है, क्योंकि उत्पीड़न और भेदभाव गैर-कानूनी हैं। बुलिंग को बर्दाश्त न करें। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो अकेले इसका सामना न करें। मदद मांगना ही इसका हल है।

-द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

सबसे आगे हम

दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के बीच चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत के जीडीपी की वृद्धि दर सबसे अधिक रही।

भारत	7.8%
चीन	5.2%
इंडोनेशिया	5.1%
अमेरिका	2.1%
जापान	1.2%

आंकड़े विकास दर के, जर्मनी में सबसे कम -0.2 प्रतिशत। | स्रोत : MoSPI

देवीदान जी ने गांव में अकाल पड़ने पर अपनी जमापूंजी से जरूरतमंदों की सेवा की और अपने दुखों को पार कर भगवान की भक्ति में जीवन समर्पित किया।

त्याग और तप

महात्मा देवीदान जी का जन्म जोधपुर में हुआ था। चार वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। वह ग्यारह वर्ष की उम्र में जोधपुर दरबार के कोठार में नौकरी करने लगे और कुछ ही दिन में अपनी योग्यता से कोठार के नायब दारोगा बन गए।

माता और दोनों भाइयों के आग्रह से बालसमंद (मंडोर) के श्रीहुक्माराम जी कछवाहा नामक एक सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध ईश्वर भक्त गृहस्थ की सुशील कन्या से देवीदान जी का विवाह हो गया। लेकिन दो वर्ष बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद देवीदान जी योग और वैद्यक का अभ्यास करने लगे। करीब एक साल बाद गांव में अकाल पड़ गया। अकाल के समय देवीदान जी ने अपनी जमापूंजी से अनाथों, भूखों और पशुओं की बड़ी सहायता की और उसी वर्ष उन्होंने गृहस्थ वस्त्र त्यागकर संत-वेश धारण किया और तप करने लगे। योग सिद्धि के लिए जोधपुर के विभिन्न स्थानों पर रहे। और आखिर में गांव के एकांत में तालाब पर आ गए। वहां एक कुटिया बनाकर भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। समय के साथ यात्रियों और रोगियों के लिए उन्होंने अपनी कुटिया के समीप बाग में 'देवीदान-देवस्थान' नामक आश्रम बनवाया।

अंतर्यात्रा
संकलित

अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए लोगों को आश्रम में सुबह के समय औषधियां दी जाती थीं, और शाम होते वहां आए लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 1 सितंबर, 1973

चीन द्वारा भारत- पाकिस्तान समझौते का स्वागत

चीनद्वारा भारत-पाक समझौते का स्वागत
चेंग फी द्वारा सम्बन्ध सामान्य होने की कामना

चीन के विदेश मंत्री पँग फी ने भारत व पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में हुए समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो दक्षिण एशिया के इन देशों के बीच संबंध सामान्य देखने के इच्छुक नहीं हैं।

गेंद न्यायपालिका के पाले में

अनुच्छेद 143 के तहत राय देना न्यायपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं है, पर बेहतर होगा कि वह राय दे, ताकि भविष्य में विवाद न हो।

सीवीपी श्रीवास्तव | **मुद्दा**

संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का संदर्भ एक ऐसा प्रावधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को देश के राजनीतिक-प्रशासनिक ढांचे के संरक्षण तक विस्तारित करता है। विधेयकों को स्वीकृति देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में राज्यपाल की भूमिका पर हाल ही में हुई बहस ने एक ऐसे मुद्दे को उभार दिया है, जिसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल है। यह मुद्दा राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोके रखने की अवधि का है। अनुच्छेद 200 में 'यथाशीघ्र' वाक्यांश का उल्लेख है, जिसके कारण तब विवाद उत्पन्न हुआ, जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव, 2023 मामले में निर्णय दिया कि विधेयकों को 'यथाशीघ्र' विधानमंडल को वापस भेजा जाना चाहिए। यदि राज्य विधानसभा विधेयक को 'संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के' पुनः प्रस्तुत करती है, तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प या विवेकाधिकार नहीं होता है, और उन्हें अपनी सहमति देनी होती है। न्यायालय ने माना कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को बिना कुछ किए रोक लेता है, तो वह संविधान का उल्लंघन होगा।

राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और इसलिए निर्वाचित नहीं, बल्कि नियुक्त होता है। जब वह राज्य के अनिर्वाचित सांविधानिक प्रमुख के रूप में, बिना किसी और विकल्प के अनुमति रोके रखने की घोषणा करके, निर्वाचित विधायिका द्वारा विधायी क्षेत्र के कामकाज को वीटो करता है, तो यह सांविधानिक लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली के भी विपरीत होगा। हालांकि अनुच्छेद 163 के तहत उसके पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, फिर भी वह संविधान के मूल दर्शन को दरकिनार नहीं कर सकता। इस बहस ने राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया है। अनुच्छेद 143 स्पष्ट करता है कि न्यायालय के लिए अपनी राय देना बाध्यकारी नहीं है। हालांकि, अनुच्छेद 143 के खंड (2) के तहत, यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय चाहता है, जो संविधान के लागू होने से पहले किसी संधि, करार, प्रसंविदा, अनुबंध, नामित या अन्य समान दस्तावेज से उत्पन्न हुआ है, तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है। इसके लिए वह अनुच्छेद 145 के खंड (3) के तहत पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। इसे ही हम सांविधानिक पीठ कहते हैं। हालांकि, यह राय किसी फैसले के विपरीत, बाध्यकारी नहीं होती।

राष्ट्रपति ने न्यायालय के आठ अप्रैल के फैसले के पांच सप्ताह बाद एक संदर्भ भेजा, जिसमें न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा विचारार्थ विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की थी। उस फैसले ने तमिलनाडु के राज्यपाल के 10 लंबित विधेयकों पर अपनी सहमति न देने के फैसले को रद्द कर दिया था। हालांकि राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं वाला संदर्भ भेजा है, लेकिन स्पष्ट है कि राज्यपाल के कार्यों का आकलन और समीक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका सवालों के घेरे में है।

हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल को भी अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति प्राप्त है, लेकिन विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या ये उन्मुक्तियां निरपेक्ष हैं। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का अनुच्छेद 361 किसी भी तरह से न्यायालयों को राज्यपाल के कार्यों की जांच करने से नहीं रोकता या निषिद्ध नहीं करता है, जिसमें आवश्यक निहितार्थ से अनुच्छेद 200 के तहत उनके कार्य भी शामिल होंगे।

क्या न्यायालय राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा थोप सकता है, यह निर्णय का विषय था, जिसके बाद अनुच्छेद 142 के प्रयोग की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया गया। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सुनिश्चित करता है, जिसके द्वारा वह संविधान के संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन ऐसी परिस्थिति में करता है, जब न तो संविधान में और न ही किसी कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान हो। राष्ट्रपति व राज्यपाल सांविधानिक प्रमुख हैं, इसलिए संविधान के प्रावधानों से बंधे हैं। उनके विवेकाधिकार, यदि कोई हों, का प्रयोग सांविधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं किया जा सकता।

हालांकि अनुच्छेद 143 के खंड (1) के तहत अपनी राय देना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि वह 'यथाशीघ्र' वाक्यांश की व्याख्या करके अपनी राय दे, ताकि भविष्य में ऐसे किसी मुद्दे पर विवाद नहीं हो और कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधाओं का सामना न करना पड़े।